PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page I

वर्ष 70 अंक 1

ISSN 2231-2439
जनवरी-जून 2026

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
नई दिल्ली

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page II

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

Estd : 1939

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डॉ. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशन्स', एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' तथा 'इण्टरनेशनल लिटरेसी ऐसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002

दूरभाषः 011–43489048

ई–मेलः directoriaea@gmail.com, iaeadelhi@gmail.com

website: www.iaea-india.com; www.iiale.org

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 1

प्रौढ़ शिक्षा

जनवरी–जून
2026
वर्ष 70 अंक 1

सम्पादक मण्डल

डा. सरोज गर्ग
श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
श्रीमती निशात फारूख

सम्पादक
सुरेश खण्डेलवाल

संयुक्त सम्पादक
राजेन्द्र जोशी

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय 2

संयुक्त सम्पादक की कलम से 4

भारत में प्रौढ़ शिक्षा की वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ एवं भविष्य की संभावनाएँ
– डॉ. विमलेश सिंह 6

वयस्कों की सामाजिक–आर्थिक एवं मानसिक चुनौतियाँ तथा समाधानः एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण
– संदीप कुमार
– डॉ. अशोक कुमार
– डॉ. सुकांत कुमार महापात्रा 16

संस्कृत साहित्य में निहित व्यावहारिक ज्ञानः श्रीमद्भगवद्गीता के संदर्भ में
– अनिता जोशी
– माया जोशी 25

उल्लास और सभी के लिए प्रौढ़ और आजीवन शिक्षा
– डॉ. सौरभ मिश्र 32

उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण : एक समग्र दृष्टिकोण
– सुरेखा खोत 44

मूल्यः 200 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 2

सम्पादकीय

भारतीय शिक्षा व्यवस्था – सवाल संतुलन का

धरती की एक छोर से दूसरे छोर तक मनुष्य यदि किसी तार से जुड़ा हुआ है तो वह प्रथम तार स्वयं प्रकृति ही है। सृजन और विनाश के अनगिनत राज प्रकृति ने स्वयं के गर्भ में छिपा रखा है। परत दर परत जिस राज को खोलने में प्रयासरत मनुष्य अपनी विकास यात्रा की अनन्त गाथा लिखता जा रहा है। शिक्षा इस विकास यात्रा का वह मौलिक आधार है जो मनुष्य को प्रकृति के सभी राज खोलने में सक्षम बनाती है। अपने पांच ज्ञानेन्द्रियों से अनुभूत स्वाद का भी भरपूर आनंद लेने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित समाज का व्याप उन मौलिक पैमानों में से एक महत्वपूर्ण पैमाना है जो विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के बीच के फासले को स्पष्ट करता है।

आज जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य सामने रख कर आगे बढ़ रहा है, तब शत–प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को अबिलम्ब हासिल करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गौरतलब है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम "उल्लास" के क्रियान्वयन के चार वर्षों (2022–2026) में हीं मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे राज्यों तथा लद्दाख एवं चंडीगढ़ जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा शत–प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना एक उम्मीद की किरण अवश्य जगाता है। पर यह कार्यक्रम भी एक निश्चित अवधि के लिए ही है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस निर्धारित अवधि अर्थात सन् 2027 तक देश शत–प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? और यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार इस कार्यक्रम की अवधि को और आगे बढ़ाएगी? क्या ऑनलाईन मोड में संचालित इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि में प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस कार्यक्रम के मौलिक स्वरूप में कुछ परिवर्तन किया जाएगा? यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार इन उपलब्धियों की वास्तविकता एवं धरातल पर इसके प्रभाव का किसी स्वतंत्र संस्थान द्वारा मूल्यांकन कराती है या नहीं?

इन प्रश्नों का उभरना इसलिए स्वाभाविक है कि अभी तक जिन उपलब्धियों का जिक्र किया जा रहा है वहां चुनौतियां तो थीं पर उनका आकार तुलनात्मकरूप में किंचित छोटा था। उदाहरण के लिए मिजोरम को लिया जा सकता है। प्रेस सूचना कार्यालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार क्लस्टर रिर्सोस सेंटर कोर्डिनेटर्स द्वारा अगस्त–सितंबर 2023 में राज्य में किए गए डोर–टू–डोर सर्वेक्षण में यहां कुल 3026 नवसाक्षर चिन्हित हुए थे। इनमें से 1692 सक्रियरूप से पढ़ने और सीखने की गतिविधियों में भाग ले रहे थे। इस प्रकार मिजोरम के शत–प्रतिशत साक्षर घोषित किए जाने का जमीनी तात्पर्य 1334 प्रौढ़ों को साक्षरता गतिविधियों से जोड़कर उन्हें साक्षर बनाना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यह संख्या और इनकी चुनौतियां कहीं बड़ी हैं।

उपरोक्त के साथ एक सवाल उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा के स्वरूप को उसकी मौलिकता,

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 3

प्रासंगिकता एवं नियोजनीयता अर्थात रोजगार प्रदान करने की क्षमता पर दूरदर्शिता के साथ समायोजन का भी है जिस पर सरकार की ओर से कोई विशेष स्पष्टता व्यक्त नहीं की गयी है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को 'सभी के लिए शिक्षा' के रूप में नामांकित किया गया है। पर बड़ा सवाल प्रौढ़ शिक्षा के तहत समाहित उच्च शिक्षा के उस आयाम का है जिसके तहत 'वयस्क शिक्षाशास्त्र' और 'विस्तार शिक्षा' के अध्ययन–अध्यापन का विषय आता है। वह विषय जिसके विविध बिंदुओं पर शोध छात्र पी.एच.डी कर अध्यापन की योग्यता प्राप्त करते हैं। आजीवन शिक्षा के बहुविषयक स्वरूप में इन शोधार्थियों के विशेषज्ञता को किस रूप में देखा जाएगा? यह सवाल अनुत्तरित है। भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का प्रारंभ से ही मानना रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा केवल साक्षरता तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका व्याप अध्ययन – अध्यापन से नवाचार और अन्वेषण तक की उच्च सीमा तक जाती है।

सरकार उच्च शिक्षा के गुणवत्ता और व्याप में समयानुकूल परिवर्तन के लिए लक्ष्य निर्धारित करती नजर आ रही है। अभी हाल ही में नीति आयोग ने भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर विस्तृत रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट कहती है कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत से विदेशों में जाने वाले छात्रों की तुलना में विदेशों से भारत आने वाले छात्रों की संख्या कहीं कम है। इसके कारण भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कई महत्वपूर्ण पैमानों पर गंभीर असंतुलन का सामना करना पड़ रहा है। संतुलन बनाने के लिए असंतुलन की तह में जाना आवश्यक है।

यदि प्रौढ़ एवं सत्त शिक्षा की ही बात करें तो दुनिया भर में यह अकादमिक विषय तेजी से आजीवन शिक्षा में तब्दील होता नजर आ रहा है। भारत में भी कई विश्वविद्यालयों ने अपने प्रौढ़, सत्त एवं विस्तार शिक्षा विभागों का नामांकरण अब आजीवन एवं विस्तार शिक्षा विभाग कर दिया है।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ देश के शैक्षिक नवोन्नमेष के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विगत 87 वर्षों से निरंतर कार्य करने वाली प्रतिनिधि संस्थान है। बदलते राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जहां उच्च शिक्षा लगातार बहु–विषयक (मल्टीडिस्पिलीनरी) होती जा रही है, यह संस्थान नवाचार सहित हर नवीन पहल का स्वागत करते हुए इन सवालों पर भी गंभीर चिंतन एवं विवेचन को आंमत्रित करती है। ताकि ट्रांजिसन के इस दौर में प्रौढ़ों के अध्ययन करने अथवा उन्हें पढ़ाये जाने व विस्तार शिक्षा की शिक्षाशास्त्र को उच्च शिक्षा क्षेत्र में उसका योग्य एवं अनिवार्य स्वरूप उपलब्ध कराया जा सके।

– सुरेश खण्डेलवाल



PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 4

संयुक्त संपादक की कलम से

सफलता की कसौटी

शिक्षा परीक्षा में हासिल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि यह समग्र विकास का माध्यम है। स्कूल, अभिभावक और समाज को मिलकर इस सोच को बदलना होगा। समस्या की जड़ यह है कि आज स्कूल और अभिभावक अक्सर नंबरों को ही सफलता का एकमात्र पैमाना बना देते हैं। इससे बच्चों की रचनात्मकता, कौशल और व्यक्गित क्षमताएं दब जाती हैं। केवल अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को श्रेष्ठ मानना पूरी तरह गलत है, क्योंकि अच्छी परवरिश की सफलता बच्चों की सोच, समझ और प्रभावी व्यवहार में निहित होती है। तुलना का दबाव बच्चों के आत्मविश्वास को तोड़ता है और चिंता–तनाव को जन्म देती है। बच्चे अपनी वास्तविक प्रतिभाओं को दबाकर केवल अंकों के पीछे भागने लगते हैं। अभिभावकों की भूमिका अपनी ईच्छाओं और अपेक्षाओं को बच्चों पर थोपने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी क्षमताओं के अनुरूप उड़ान भरने देना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी दिशा में समग्र विकास पर बल देती है, जहां ज्ञान अर्जन के साथ जीवन–कौशल महत्वपूर्ण है। यह नीति छात्रों के मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास को प्राथमिकता देती है, न कि केवल अंकों को। जरूरत इस बात की है कि अभिभावक बच्चों की आवश्यकताओं को समझें और उनकी कमजोरियों को बार–बार उनके सामने न दोहराएं। बच्चे में मौजूद हुनर को बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए। अभिभावकों को सकारात्मक सोच रखते हुए जागरूक रहना होगा और सुविधाओं की अति करने से बचना होगा। परीक्षा के दौरान घर–परिवार में सामान्य वातावरण बनाना प्राथमिक जरूरत है, ताकि बच्चों में परीक्षा का भय न पैदा हो। सामान्य दिनों की तरह व्यवहार करना चाहिए, जिससे डर उनकी कमजोरी न बने। भावनात्मक समर्थन के लिए खुला सवांद जरूरी है।

नई शिक्षा नीति कहती है कि अधिकांश कक्षाओं में ऐसे बच्चों की पहचान होनी चाहिए, जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है और जिन्हें लगातार मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में सामने आया है कि उन बच्चों की जितनी जल्दी मदद शुरू की जाती है, आगे प्रगति की संभवाना उतनी ही बेहतर नजर आती है। अध्यापकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार की अक्षमताओं की पहचान करने और उनके निवारण के लिए योजना बनाने में विशेषरूप से मदद मिलती है, तो विशिष्ट कार्यों और उपयुक्त तकनीक की मदद से कुछ प्रयास शामिल किए जा सकते हैं। बच्चों को अपनी गति के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता देना, पाठयक्रम को सभी बच्चों के लिए सक्षम और लचीला बनाना तथा उपयुक्त आंकलन एवं प्रमाणन के लिए अनुकूल माहौल बनाना आज के समय की जरूरत है।

ऐसे में नंबर के गणित के बजाय क्षमतावान बनाने की जरूरत होनी चाहिए। सीखने की क्षमता वाले

सभी छात्रों के लिए समान पंहुच और दृष्टि में बदलाव सुनिश्चित की जाय तो अंकों की असमानता दूर की जा सकती है। यह भी देखना होगा की बच्चों की समझ और उनकी प्रवृत्ति के मद्देनजर पाठ्यक्रम की उपलब्धता होनी चाहिए। अनेक बार भाषा की बड़ी समस्या होती है। बच्चे मातृभाषा में अधिक सहज होते हैं, लेकिन अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं थोपने के कारण बच्चा असहज महसूस करता है और धीरे–धीरे वह पढ़ाई से ही दूरी बनाने लगता है। अच्छे नंबर और बेहतर परिणाम के लिए सहज भाव और अनुकूल वातावरण का निर्माण आवश्यक है।

सार्थक संवाद से बच्चे भावनात्मकरूप से मजबूत होंगे और उनकी सोच को सकारात्मक आकार मिलेगा। अभिभावक, परिवार, समाज, स्कूल के बच्चों की तुलना अंकों से करते हैं, न कि उनके कौशल और प्रभावी व्यवहार से। इससे मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। पालन–पोषण या परवरिश की व्यवस्था सीखाती है कि अभिभावकों की भूमिका बच्चों की सोच और उनके भीतर जागरूकता विकसित करना है। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक कक्षा में अंकों से तुलनात्मक समझ विकसित नहीं करना चाहिए। शैक्षणिक विकास में बच्चों की समझ, अभिव्यक्ति और सोच के आधार पर उन्हें गले लगाने की जरूरत है। अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर थोपने से उनका मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास कमजोर होता जा रहा है। अभिभावक और अध्यापकों को शैक्षणिक गतिविधियों में मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अंकों के आधार पर मूल्यांकन के स्थान पर बच्चों के संग सार्थक संवाद को प्राथमिकता देना चाहिए।

परीक्षा के समय तनाव आम समस्या है, जो एकाग्रता और याददाश्त को प्रभावित करता है। अभिभावाकों को बच्चों को शांत रखने के उपाय अपनाने चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और स्क्रीन की अवधि सीमित रखना प्राथमिकता होना चाहिए। श्वांस व्यायाम सिखाना चाहिए, जो तनाव को कम करता है। इससे बच्चे तर्क संगत तरीके से परीक्षा चिंताओं से निपट सकते हैं। अभिभावकों को घर पर सीखने का समर्थन करने, शिक्षकों से संवाद रखने और मूल्यों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बच्चों की समस्याओं को सुनकर अभिभावक – अध्यापक सामूहिक प्रयास करें, तो बच्चे का मानसिक विकास तेज होगा। अधिक अंक वाली सोच बदलने की जरूरत है। समाज का दायित्व अगर हमने आज नहीं बदला, तो आने वाली पीढ़ियां अंकों के बोझ तले दब जाएंगी। शिक्षा को अंकों का खेल बनाने से बचने की जरूरत है। अभिभावक, शिक्षक और समाज को मिलकर बच्चों को प्यार, समझ और कौशल से गढ़ना चाहिए। सकारात्मक माहौल बनाकर रूचियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे और दीर्घकालिक सफलता पाएंगे।

– राजेंद्र जोशी



PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 6

भारत में प्रौढ़ शिक्षा की वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ एवं भविष्य की संभावनाएँ

– **विमलेश सिंह**

पूर्ण मानव क्षमता को सृजित कर किसी भी राष्ट्र को विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर करने हेतु एक अनिवार्य शर्त है शिक्षा। साक्षरता या कहें बुनियादी शिक्षा, यह जीवनपर्यन्त शिक्षा के अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर व्यक्ति के समग्र विकास को आभायुक्त करती है। निरक्षरता देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यद्यपि भारत सरकार द्वारा निरक्षरता को समाप्त करने हेतु निरंतर प्रशंसनीय कार्य किये जाते रहे हैं तथापि भारत उन विकासशील देशों की श्रेणी में है, जहाँ पर यह समस्या आज भी विद्यमान है। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य उन वयस्क व्यक्तियों को शिक्षा का विकल्प देना है जिन्होंने शिक्षा का अवसर किसी कारण से गंवा दिया है और वह औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की आयु को पार कर चुके हैं, लेकिन अब वे साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, कौशल विकास (व्यावसायिक शिक्षा) और इसी तरह के अन्य ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हैं।

15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर–साक्षर लोगों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करना ही प्रौढ़ शिक्षा की प्राथमिकता है। प्रौढ़ शिक्षा हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह वयस्क व्यक्तियों को नए कौशल सीखने, अपने ज्ञान का विस्तार करने और अपने करियर की संभावनाओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। प्रौढ़ शिक्षा किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत में एक बड़ा वर्ग ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से औपचारिक शिक्षा से वंचित रहा है। इस शोध पत्र में भारत में प्रौढ़ शिक्षा की वर्तमान स्थिति, इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सरकारी प्रयासों के बावजूद अभी भी इस राह में कई बाधाएँ मौजूद हैं, जिन्हें दूर कर प्रौढ़ शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

कूटशब्द : प्रौढ़ शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, भारत में प्रौढ़ शिक्षा की वर्तमान स्थिति, प्रौढ़ शिक्षा हेतु कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा की चुनौतियाँ तथा भविष्य की संभावनाएं।

प्रस्तावना

शिक्षा हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है और यह समाज में समानता और विकास की कुंजी है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में कई लोग गरीबी, सामाजिक बाधाओं या अवसरों की कमी के कारण अशिक्षित ही रह जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ने–लिखने और जीवनोपयोगी ज्ञान प्रदान करने का कार्य प्रौढ़ शिक्षा करती है। यह वयस्कों को जागरूक, आत्मनिर्भर और समाज में सक्रिय

भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। प्रौढ़ शिक्षा से व्यक्ति में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। यह उसे अपने काम और प्रयास का सही मूल्य समझने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, शिक्षित वयस्क स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, कृषि, आर्थिक योजनाओं और सामाजिक मुद्दों के प्रति भी जागरूक होते हैं। प्रौढ़ शिक्षा न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुधारती है, बल्कि समाज में समरसता, ज्ञान और विकास को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

प्रौढ़ शिक्षा किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत में एक बड़ा वर्ग ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से औपचारिक शिक्षा से वंचित रहा है। इस शोध पत्र में भारत में प्रौढ़ शिक्षा की वर्तमान स्थिति, इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सरकारी प्रयासों के बावजूद अभी भी कई बाधाएँ मौजूद हैं, जिन्हें दूर कर प्रौढ़ शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

प्रौढ़ शिक्षा वयस्क निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ वयस्क (15–35 वर्ष) या इससे बड़े व्यक्तियों को शिक्षित करना जो बचपन में शिक्षा से वंचित रह गए हों। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें पढ़ना–लिखना, गिनती करना और जीवन से जुड़ी आवश्यक जानकारियाँ सिखाना है। इससे व्यक्ति आत्मनिर्भर, जागरूक और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनता है। प्रौढ़ शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का साधन है, बल्कि सामाजिक प्रगति की नींव भी है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध पत्र का उद्देश्य केवल प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों का गहन एवं समग्र विश्लेषण करना है। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- भारत में प्रौढ़ शिक्षा की वर्तमान स्थिति, उसकी चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- प्रौढ़ शिक्षा की वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत भारत में प्रौढ़ साक्षरता दर, सरकारी कार्यक्रमों एवं उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
- प्रौढ़ शिक्षा के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों के अन्तर्गत यह जांचना कि प्रौढ़ शिक्षा किस प्रकार सामाजिक जागरूकता, रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करती है।
- प्रौढ़ शिक्षा के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना जैसे गरीबी, लैंगिक असमानता, संसाधनों की कमी, डिजिटल विभाजन आदि।

अनुसंधान पद्धति

इस शोध में अपनाई गई पद्धति सरल, विश्वसनीय एवं विश्लेषणात्मक है, जो प्रौढ़ शिक्षा की वास्तविक स्थिति को समझने में सहायक है। यह शोध मुख्यतः गुणात्मक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर

आधारित है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया गया है। इसमें शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट्स, जनगणना के आंकड़े, शिक्षा नीतियों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से संबंधित तथ्य, शोध पत्रों तथा विभिन्न प्रकाशनों का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। वर्णनात्मक भाग में भारत में प्रौढ़ शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वहीं विश्लेषणात्मक भाग में चुनौतियों एवं संभावनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

भारत में प्रौढ़ शिक्षा की वर्तमान स्थिति

भारत एक विकासशील देश है जहाँ राष्ट्र की प्रगति का आधार शिक्षा है। लेकिन आज भी यहाँ की बड़ी आबादी अशिक्षा से ग्रस्त है, जिसके कारण देश के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में प्रौढ़ शिक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह वयस्कों को ज्ञान, जागरूकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में आज भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग निरक्षर हैं। निरक्षरता के कारण वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अनजान रहते हैं और अक्सर ठगी, अन्याय या सामाजिक भेदभाव का शिकार बन जाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा उन्हें सशक्त बनाती है, आत्मसम्मान देती है और जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। शिक्षित होकर वे समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकते हैं और अपने परिवार तथा समुदाय के विकास में सक्रिय योगदान दे सकते हैं।

शिक्षा मंत्रालय (2022) द्वारा प्रदत्त जानकारी के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गैर–साक्षरों की कुल संख्या 25.76 करोड़ (पुरुष 9.08 करोड़, महिला 16.68 करोड़) है। 2009–10 से 2017–18 के दौरान साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत साक्षर के रूप में प्रमाणित व्यक्तियों की 7.64 करोड़ की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में भारत में लगभग 18.12 करोड़ वयस्क अभी भी गैर–साक्षर हैं। भारत में प्रौढ़ शिक्षा की स्थिति को समझने के लिए साक्षरता दर, सरकारी प्रयास, सामाजिक असमानताएँ और हाल के रुझानों का विश्लेषण आवश्यक है। वर्तमान समय में भारत ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई असमानताएँ बनी हुई हैं, जो निम्न प्रकार हैं :

प्रौढ़ साक्षरता दर की वर्तमान स्थितिः भारत में प्रौढ़ शिक्षा की स्थिति को समझने का सबसे प्रमुख आधार साक्षरता दर है। वर्ल्ड बैंक (2023) के हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रौढ़ साक्षरता लगभग 81.7 प्रतिशत तक आंकी गई है जिसमें पुरूष साक्षरता दर लगभग 88.3 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर लगभग 74.9 प्रतिशत है। वहीं 2011 में वर्ल्ड बैंक ने भारत की प्रौढ़ साक्षरता लगभग 69.1 प्रतिशत दर्ज की थी। 1981 में यह दर लगभग 40.76 प्रतिशत थी, (जिसमें पुरूष साक्षरता दर लगभग 54.84 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर लगभग 25.68 प्रतिशत थी) जो अब दोगुनी से अधिक हो चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में प्रौढ़ शिक्षा में निरंतर सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी वैश्विक औसत (लगभग 87 प्रतिशत) से कम है।

लैंगिक असमानताः भारत में प्रौढ़ शिक्षा की स्थिति पुरुष और महिलाओं के बीच समान नहीं है। वर्ल्ड बैंक (2023) के आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रौढ़ साक्षरता दर में पुरुष–महिला अन्तर 13.4 प्रतिशत है। ग्रामीण महिलाओं में निरक्षरता सबसे अधिक देखी जाती है। यह दर्शाता है कि प्रौढ़ शिक्षा अभी भी महिला सशक्तिकरण से सीधे जुड़ी हुई समस्या है।

ग्रामीण–शहरी अंतरः भारत में प्रौढ़ शिक्षा की स्थिति में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट और गहरी खाई मौजूद है। आवदिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस) 2023–24 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर अधिक है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता अधिक है। इसके प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी (शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण केंद्रों की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है), डिजिटल साक्षरता की पहुंच का आभाव (शहरी भारत में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की पहुंच कहीं अधिक है, जो आज के समय में प्रौढ़ शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है), शिक्षकों की गुणवत्ता और उपलब्धता में कमी (ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर योग्य शिक्षकों की कमी होती है, क्योंकि अधिकांश शिक्षक बेहतर सुविधाओं के कारण शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग को प्राथमिकता देते हैं), तथा आर्थिक और सामाजिक कारण (ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि में संलग्नता और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ने 'ड्राप आउट' की दर अधिक) आदि हैं। महिलाओं के मामले में, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक दबाव और घर के कामों में व्यस्तता प्रौढ़ शिक्षा में बड़ी बाधा बनती है। शिक्षा संसाधनों की कमी, गरीबी के कारण रोजगार की प्राथमिकता, जागरूकता का अभाव आदि के कारण ग्रामीण भारत में प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है।

राज्यवार असमानताएँ : भारत में विभिन्न राज्यों के बीच प्रौढ़ साक्षरता दर में काफी अंतर है। केरलम में कुल प्रौढ़ साक्षरता दर लगभग 96.2 प्रतिशत है से 97 प्रतिशत सबसे अधिक है। केरलम में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का अंतर केवल 2.2 प्रतिशत न्यूनतम लैंगिक अंतर है, जो राष्ट्रीय औसत (लगभग 12–14 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम है। यहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच साक्षरता का अंतर लगभग समाप्त हो चुका है (मात्र 1.5 प्रतिशत का अंतर)। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSO) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी.एल.एफ.एस 2023–24) के आंकड़ों के आधार पर आंध्र प्रदेश भारत में सबसे कम साक्षरता दर (लगभग 72.6 प्रतिशत) वाला राज्य है। राजस्थान में महिला साक्षरता (लगभग 65.8 प्रतिशत) की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच सबसे बड़ा अंतर 20.1 प्रतिशत देखा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम लगभग 84.2 प्रतिशत (पी.एल.एफ.एस 2023–24) है। बिहार की कुल साक्षरता दर लगभग 74.3 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि प्रौढ़ शिक्षा का स्तर क्षेत्रीय विकास से जुड़ा हुआ है।

सामाजिक वर्गों के बीच अंतरः भारत में प्रौढ़ शिक्षा की स्थिति सभी वर्गों में समान नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों में साक्षरता दर कम है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शिक्षा से अधिक वंचित है। इससे स्पष्ट है कि प्रौढ़ शिक्षा केवल शैक्षिक नहीं, बल्कि

सामाजिक न्याय और समानता का मुद्दा भी है।

भारत जैसे देश में प्रौढ़ शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ

भारत में प्रौढ़ शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई बाधाएँ मौजूद हैं। एक विशाल जनसंख्या, विविध सामाजिक संरचना और आर्थिक असमानताओं के कारण प्रौढ़ शिक्षा को लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियाँ इस क्षेत्र में सामने आती हैं :

1. **व्यापक निरक्षरता:** भारत में व्यापक निरक्षरता फैली हुई है। नगरों की अपेक्षा गाँवों में निरक्षरता का अधिक बोलबाला है। जब तक निरक्षरता की समस्या बनी रहेगी, तब तक न ही प्रौढ़ों में नवचेतना उत्पन्न की जा सकती है और न ही देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति की कल्पना।

2. **आर्थिक समस्या:** भारत में प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 2025–2026 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, भारत की जनसंख्या 146–147 करोड़ के बीच पहुंच गई है। यह जनसंख्या वृद्धि दर के साथ दुनिया की कुल आबादी का लगभग 17–18 प्रतिशत हिस्सा है। इतनी विशाल जनसंख्या में प्रौढ़ों को साक्षर बनने के लिए इतने अधिक धन की आवश्यकता है, जिसकी समुचित व्यवस्था कर पाना सरकार के लिए काफी कठिन है। इसके साथ ही प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए पर्याप्त अध्यापकों तथा समाज शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था करना भी एक कठिन कार्य है।

3. **पाठ्यक्रम की समस्या:** प्रौढ़ शिक्षा की तीसरी समस्या पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है। प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में विद्वानों में परस्पर मतभेद है। प्रौढ़ों की रुचियाँ तथा आवश्यकताएँ बालकों की रुचियों तथा आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं। ऐसी दशा में बालकों का पाठ्यक्रम प्रौढ़ों के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। कुछ प्रौढ़ व्यक्ति पूर्णतया निरक्षर होते हैं, कुछ अर्द्ध–शिक्षित तथा कुछ नव साक्षर, इन सभी के लिए पृथक–पृथक् पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना एक कठिन कार्य है। इस प्रकार प्रौढ़ों की रुचियों के अनुकूल साहित्य का हमारे देश में अभाव है और विभिन्न आयु के प्रौढ़ों के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करना एक जटिल समस्या है।

4. **योग्य अध्यापकों की कमी:** प्रौढ़ शिक्षा का कोई कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है, जब कि वह प्रौढ़ मनोविज्ञान के ज्ञाता अध्यापकों द्वारा संचालित हो, परन्तु हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के ज्ञाता शिक्षकों का अभाव है। अधिकतर शिक्षक प्रौढ़ शिक्षा की समस्याओं, उद्देश्यों तथा प्रौढ़ मनोविज्ञान से पूर्णतया अपरिचित होते हैं। ऐसी दशा में इनसे सफलतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करने की आशा करना व्यर्थ है। प्रौढ़ शिक्षा को सफल बनाने के लिए लाखों प्रौढ़ मनोविज्ञान के ज्ञाता अध्यापकों की आवश्यकता होगी जिनकी

पूर्ति करना एक कठिन कार्य है।

5. **शिक्षा के साधनों की कमीः** प्रौढ़ शिक्षा के साधनों से तात्पर्य वह समूह अथवा संस्थाएँ हैं, जो प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क रखती हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान कर उनकी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करती हैं। इस दृष्टि से उत्तम फिल्मों, चार्ट व चित्र तथा अन्य दृश्य सामग्री की परम आवश्यकता है, परन्तु इन साधनों को जुटाना कोई सरल कार्य नहीं है।

6. **उपयुक्त साहित्य की कमीः** प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य प्रौढ़ों को केवल साक्षर बनाना ही नहीं है, वरन् समाज का एक जागरूक तथा उत्तरदायी सदस्य बनाना है, उनमें नवचेतना भरना तथा उनके दृष्टिकोण को आलोचनात्मक बनाना है, परन्तु ऐसा करने के लिए उनके अनुकूल एक श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली साहित्य के सृजन की आवश्यकता है, लेकिन साहित्य का निर्माण करने और उसके प्रकाशन की व्यवस्था करना भी एक जटिल समस्या है।

7. **शिक्षण पद्धति की समस्याः** प्रौढ़ों की बुद्धि परिपक्व होती है। अतः उन्हें बालकों के समान नहीं पढ़ाया जा सकता। इसके अतिरिक्त जीवन तथा समाज के प्रति प्रौढ़ों का दृष्टिकोण समान नहीं होता है। प्रौढ़ समाज के पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं और उनके विरुद्ध कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रौढ़ों के लिए किसी उपयोगी शिक्षण–पद्धति का निर्माण करना एक कठिन कार्य है।

8. **समाज शिक्षा केन्द्रों पर उपस्थिति की समस्याः** सामाजिक शिक्षा केन्द्रों पर प्रौढ़ प्रायः अनुपस्थित रहते हैं। इसका मूल कारण शिक्षा के प्रति उदासीनता है। प्रौढ़ों की अनुपस्थिति में सामाजिक शिक्षा केन्द्रों पर आयोजित किये गये कार्यक्रमों का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है।

9. **प्रौढ़ शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व की समस्याः** प्रौढ़ शिक्षा की एक अन्य समस्या यह है कि प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व किसका है? केन्द्र सरकार ने इस उत्तरदायित्व का भार राज्य सरकारों पर डाल रखा है, लेकिन शिक्षा परिषद् और शिक्षा विभाग इसके प्रति पूर्ण उदासीन हैं। ऐसी दशा में सामाजिक उपेक्षा से प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार की अपेक्षा करना व्यर्थ है।

10 **प्रौढों के निराशावादी तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण की समस्याः** भारतीय प्रौढ़ निराशावादिता, रूढ़िवादिता तथा सन्देहों से ग्रस्त होते हैं। प्रायः प्रौढ़ सोचते हैं कि इतनी आयु बीत चुकी है, अब पढ़–लिखकर क्या ही होगा? इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा को वे केवल जीविका का साधन मानते हैं। अतः जब वे पढ़े–लिखे नौजवानों को बेरोजगार देखते हैं, तो शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाते हैं। वास्तव में प्रौढ़ों का यह निराशावादी दृष्टिकोण प्रौढ़ शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर आता है। प्रौढ़ व्यक्तियों में सीखने की प्रेरणा कम होती है, शिक्षा को अनावश्यक समझना साथ ही निरंतरता बनाए रखना प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए कठिन होता है।

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 12

11 **सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएँ:** समाज में प्रौढ़ शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव, पारंपरिक सोच और रूढ़िवादिता तथा यह धारणा कि "अब पढ़ाई की उम्र निकल चुकी है" इसके कारण प्रौढ़ लोग शिक्षा ग्रहण करने में रुचि नहीं लेते और शिक्षा ग्रहण करने से कतराते हैं।

12. **गरीबी और बेरोजगारी:** गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोग शिक्षा के बजाय रोजगार को प्राथमिकता देते हैं। दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के पास समय की कमी होती है। शिक्षा से तुरंत आर्थिक लाभ न दिखने के कारण प्रौढों की रुचि इसमें कम ही रहती है।

13. **लैंगिक असमानता:** भारतीय समाज में पुरूषों की तुलना में महिलाओं को शिक्षा के अवसर कम ही मिलते हैं। वहीं घरेलू कार्यों और सामाजिक प्रतिबंधों के कारण महिलाएँ शिक्षा से वंचित रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है।

14. **ग्रामीण–शहरी असमानता:** ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा केंद्रों और संसाधनों की कमी, शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम जागरूकता, दूर–दराज के क्षेत्रों में पहुंच की समस्या भी प्रौढ़ शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है।

15. **अधोसंरचना की कमी:** पर्याप्त शिक्षा केंद्रों का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों और स्वयंसेवकों की कमी एवं शिक्षण सामग्री और संसाधनों की कमी भी प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में बाधा उत्पन्न करती है।

16. **डिजिटल विभाजन:** आज के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के युग में भी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी साधनों की कमी, तथा बुजुर्गों में डिजिटल ज्ञान का अभाव है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ व्यक्तियों को ऑनलाइन शिक्षा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

17. **प्रशासनिक और नीतिगत समस्याएँ:** योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाना, निगरानी और मूल्यांकन की कमी तथा विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय का अभाव प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार को बाधित करता है।

भारत में प्रौढ़ शिक्षा हेतु सरकारी कार्यक्रम एवं प्रयास

भारत में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने समय–समय पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएँ शुरू की, जिनका उद्देश्य केवल साक्षरता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि वयस्कों को जीवनोपयोगी कौशल, जागरूकता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना भी है। भारत सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाएं गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्न हैं :

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988: राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1988 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य 15–35 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षरों को साक्षर बनाना, पढ़ना,

लिखना और गणना (3 आरः रीडिंग, रायटिंग, एरिथमेटिक) सिखाना तथा सामाजिक जागरूकता बढ़ाना था।

साक्षर भारत कार्यक्रम 2009: साक्षर भारत कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाना और समाज में शिक्षा के स्तर को सुधारना था। इस कार्यक्रम की शुरुआत 8 सितंबर 2009 (अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस) को की गई थी। यह कार्यक्रम पहले के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का ही विस्तारित रूप है। इसका मुख्य फोकस महिलाओं की साक्षरता को बढ़ाने पर था, क्योंकि भारत में महिला निरक्षरता दर अधिक पाई जाती है। इसका उद्देश्य वयस्कों (15 वर्ष से अधिक आयु) को बुनियादी साक्षरता प्रदान करना, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाना, पढ़ना, लिखना और गणना (3 आर स्किल) सिखाना, सामाजिक जागरूकता और जीवन कौशल विकसित करना, निरक्षरता दर को कम करना था। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन जिलों में लागू किया गया जहाँ महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम थी।

पढ़ना–लिखना अभियान 2020: इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत चलाए गए प्रयासों का ही उन्नत रूप है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वयस्कों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करना और उन्हें दैनिक जीवन के लिए सक्षम बनाना है। यह कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका लक्ष्य 15 वर्ष से अधिक आयु के उन व्यक्तियों को साक्षर बनाना है, जो पढ़ना–लिखना नहीं जानते। इसका उद्देश्य वयस्कों को बुनियादी साक्षरता (Reading & Writing) प्रदान करना, संख्यात्मक ज्ञान (Numeracy Skills) विकसित करना, लोगों को दैनिक जीवन के कार्यों में सक्षम बनाना, सामाजिक और आर्थिक जागरूकता बढ़ाना, ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यमों का उपयोग, सरल और स्थानीय भाषा में शिक्षण, लचीली समय–सारणी, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।

न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (NILP): न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 के लिए की गई है। यह कार्यक्रम पहले के "पढ़ना–लिखना अभियान" का विस्तारित और उन्नत रूप है। इसका लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर–साक्षर व्यक्तियों को शिक्षित करना है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (NILP) भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक नवीन प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश के वयस्क निरक्षरों को साक्षर बनाना और उन्हें जीवनोपयोगी कौशल प्रदान करना है। यह कार्यक्रम आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक साक्षरता से आगे बढ़कर डिजिटल और कार्यात्मक साक्षरता पर भी जोर देता है। इसका लक्ष्य लगभग 5 करोड़ वयस्कों को साक्षर बनाना है।

भारत में प्रौढ़ शिक्षा की भविष्य की संभावनाएँ

भारत में प्रौढ़ शिक्षा की भविष्य की संभावनाएँ अत्यंत व्यापक और सकारात्मक हैं। यह केवल साक्षरता तक सीमित न रहकर अब सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 और साक्षर भारत कार्यक्रम 2009 ने वयस्कों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 ने इसे और अधिक सशक्त दिशा प्रदान की है। एनईपी 2020 में डिजिटल साक्षरता, वित्तीय जागरूकता और कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया है। डजिटल तकनीक के विकास के कारण सीखने की प्रक्रिया अब और भी सरल और सुलभ हो गई है। डिजिटल तकनीक ने प्रौढ़ शिक्षा को पूरी तरह बदल दिया है। अब मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं भी और कभी भी सीख सकता है। DIKSHA App और SWAYAM जैसे प्लेटफॉर्म इस दिशा में क्रांतिकारी कदम हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑनलाइन लर्निंग के बढ़ते उपयोग से यह क्षेत्र और भी सशक्त होगा। इसके साथ ही स्किल इंडिया मिशन 2015 जैसे कार्यक्रम वयस्कों को रोजगारपरक कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और जीवन स्तर सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शिक्षित महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं और परिवार के विकास में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021–22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022–2027 की अवधि के लिए 'न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम)' को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने की सिफारिशें शामिल हैं। 'प्रौढ़ शिक्षा' के स्थान पर 'सभी के लिए शिक्षा' शब्द का प्रयोग किया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। इससे स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण, और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। अतः कहा जा सकता है कि भविष्य में प्रौढ़ शिक्षा एक जागरूक और जिम्मेदार समाज के निर्माण का आधार होगी।

निष्कर्ष

प्रौढ़ शिक्षा केवल पढ़ना–लिखना सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता, समानता और परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब प्रत्येक वयस्क शिक्षित होगा, तभी भारत वास्तव में "विकसित भारत" बन सकेगा। शिक्षित व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सुधारता है, बल्कि परिवार और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। देश की प्रगति के लिए हर व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए हमें हर घर में शिक्षा पहुँचाने और सभी वयस्कों को साक्षर बनाने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि समाज और राष्ट्र दोनों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

प्रौढ़ शिक्षा से न केवल व्यक्ति आत्मनिर्भर और जागरूक बनता है, बल्कि पूरा समाज भी लाभान्वित

होता है। शिक्षा समानता, सामाजिक विकास और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग खोलती है। इसलिए हर शिक्षित व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह अन्य वयस्कों और बुजुर्गों को शिक्षित करने में मदद करे। इसी तरह के निरंतर प्रयासों से ही हमारा देश "पूर्ण साक्षर भारत" बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, समयाभाव और डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं, फिर भी निरंतर प्रयासों और तकनीकी प्रगति के कारण भविष्य में प्रौढ़ शिक्षा भारत के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ सिद्ध होगी।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति : प्रौढ़ शिक्षा।
3. अग्रवाल, जे. सी. (2009). भारत में प्रौढ़ शिक्षा, विद्या विहार, नई दिल्ली।
4. छाबड़ा, सुनिधि (2012). किशोर और प्रौढ़ शिक्षा Manohar Publishers & Distributors
5. Kumari, Dr. Sarita (2025). Contemporary History of Adult Education, Ayushman Publication House.
6. Baviskar, Dr. S. G. (2016). Adult Education in India, Oxford Book Company.
7. Education Ministry Press Release: Press Information Bureau 16 February 2022.
8. Periodic Labour Force Survey 2023-24, NSO, MoSPI.
9. Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2022). National Statistical Office Report on Education, Government of India.
10. UNESCO Institute for Statistics. (2021). Adult and Youth Literacy Rates (India). UNESCO.
11. NITI Aayog. (2021). Strategy for New India @75: Education Sector. Government of India.
12. Ministry of Rural Development. (2020). Shyama Prasad Mukherji Urban Mission Report. Government of India.

❍❍❍❍❍

"स्त्री ही इस संसार और कथित सभ्यता की संजीवनी और आशा है क्योंकि सृष्टि और मानव मन के भीतर जो देवी और आसुरी शक्तियां संघर्षरत हैं उनके संतुलन का सूत्र और रहस्य स्त्री के पास है पुरूष के पास नहीं।"

– प्रख्यात रचनाकार जयशंकर प्रसाद

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 16

वयस्कों की सामाजिक–आर्थिक एवं मानसिक चुनौतियाँ तथा समाधान : एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

– संदीप कुमार
– अशोक कुमार
– सुकांत कुमार महापात्रा

मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में से वयस्क अवस्था विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण होती है, जिसमें व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक भूमिकाओं के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। वर्तमान संदर्भ में वयस्क व्यक्तियों के सामने अनेक सामाजिक–आर्थिक चुनौतियाँ जैसे बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, कार्य असंतुलन, सामाजिक दबाव तथा मानसिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं। निश्चितरूप से इन चुनौतियों का प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत संबंधों और जीवन संतुष्टि पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रस्तुत लेख में वयस्क मनोविज्ञान की अवधारणा, प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में सभी चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही समाधान के रूप में व्यक्तिगत, सामाजिक और नीतिगत हस्तक्षेपों पर चर्चा की गई है। प्रस्तुत आलेख में मनोविज्ञानिक विश्लेषण द्वारा यह समझने का प्रयास किया गया है कि वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक–आर्थिक स्थिरता के लिए बहु–स्तरीय दृष्टिकोण क्यों आवश्यक है।

मुख्यबिन्दुः वयस्क मनोविज्ञान, सामाजिक–आर्थिक चुनौतियाँ, मानसिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, आजीवन शिक्षा, तनाव प्रबंधन।

भूमिका

मानव विकास का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र वयस्क मनोविज्ञान है जो वयस्क अवस्था में व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं, सामाजिक भूमिकाओं और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह अवस्था किशोरावस्था के बाद प्रारंभ होती है और इसमें व्यक्ति अपने जीवन की अनेक जिम्मेदारियों जैसे पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बखूबी निभाता है। निःसंदेहरूप से 21वीं सदी में वैश्वीकरण, तकनीकी विकास, प्रतिस्पर्धा और शहरीकरण ने वयस्क जीवन को असहज बना दिया है। आज का वयस्क केवल व्यक्तिगत विकास ही नहीं, बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं और आर्थिक दबावों के बीच संतुलन बनाने में संघर्षरत रहता है। इसी कारण मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और असंतोष जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। भारत जैसे विकासशील देश में यह समस्या और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जहाँ एक ओर सामाजिक एवं आर्थिक असमानता है और दूसरी ओर तकनीकी प्रभाव के चलते तेजी से बदलते रहन – सहन के तौर तरीके

व पारंपरिक व्यवसायों में बदलाव प्रमुख कारण हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 ने वयस्क शिक्षा और आजीवन सीखने पर बल देकर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति–ढांचा प्रस्तुत किया है।

वयस्क मनोविज्ञान की अवधारणा

वयस्क मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है, जो वयस्क अवस्था में व्यवहार, सामाजिक भूमिकाओं और निर्णय लेने की क्षमताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। ये समझने का प्रयास करती है कि वयस्क अपने जीवन के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक संदर्भों में किस प्रकार सोचते हैं, और अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित करते हैं। वयस्कता को सामान्यतः एक ऐसी अवस्था माना जाता है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक दृष्टि से परिपक्व होता है तथा जीवन के प्रति अधिक उत्तरदायी बन जाता है।

वयस्क मनोविज्ञान की परिभाषा

वयस्क मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है –

"यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो वयस्कों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारात्मक विकास का अध्ययन करती है तथा यह विश्लेषण करती है कि वे अपने जीवन के अनुभवों, जिम्मेदारियों और सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर किस प्रकार निर्णय लेते हैं और अनुकूलन करते हैं।"

वयस्कों की विशेषताएँ

- **आत्म–निर्देशित व्यवहार** : वयस्क जीवन के निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होते हैं। वे बाहरी निर्देशों पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने अनुभव, ज्ञान और परिस्थितियों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। यह उन्हें जिम्मेदार और स्वायत्त बनाने में सक्षम होती है।
- **अनुभव आधारित निर्णय** : वयस्कों की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं। जीवन के विविध अनुभव उनके सीखने के प्रमुख स्रोत होते हैं, जो उनकी समस्या–समाधान क्षमता को व्यावहारिक बनाते हैं।
- **जिम्मेदारी और भूमिका संतुलन** : वयस्क अनेक भूमिकाएँ निभाते हैं जैसे परिवार में माता–पिता, कार्यस्थल पर कर्मचारी, और समाज में एक अच्छे नागरिक की भूमिका। इन सभी भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाए रखना उनकी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक चुनौती होती है। यह संतुलन उनकी मानसिक स्थिरता और सामाजिक अनुकूलन को प्रभावित करता है।

मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में वयस्कों के व्यवहार

वयस्कों की सामाजिक – आर्थिक समस्याओं एवं व्यवहार को समझने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि ये सिद्धांत हमें यह समझने में सहायक होते हैं कि वयस्क अपने जीवन में आने वाली सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक चुनौतियों का सामना किस प्रकार करते हैं। इस संदर्भ में एरिक एरिक्सन तथा अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत विशेष रूप से उपयोगी हैं, जो वयस्क

व्यवहार और प्रेरणा को समझने के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं।

1. एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांतः एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत मानव जीवन को आठ विकासात्मक चरणों में विभाजित करता है, जिनमें वयस्क अवस्था के चरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। एरिक्सन के अनुसार वयस्क जीवन में व्यक्ति दो प्रमुख मनोसामाजिक संघर्षों का सामना करता हैः

संबंध बनाम अकेलापनः इस चरण में व्यक्ति का प्रमुख कार्य घनिष्ठ और अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करना होता है। यदि व्यक्ति सफलतापूर्वक प्रेमपूर्ण, सामाजिक और पारिवारिक संबंध बना पाता है, तो उसमें भावनात्मक संतुलन और सुरक्षा की भावना विकसित होती है। इसके विपरीत, यदि वह संबंध स्थापित करने में असफल रहता है, तो वह अकेलेपन, अलगाव और भावनात्मक अस्थिरता का अनुभव करता है। आधुनिक समय में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कार्यभार और डिजिटल दूरी के कारण यह संघर्ष और अधिक तीव्र हो गया है।

उत्पादकता बनाम ठहरावः इस चरण में वयस्क व्यक्ति का उद्देश्य समाज और अगली पीढ़ी के लिए योगदान देना होता है। यह योगदान पालन–पोषण, कार्य, शिक्षण या सामाजिक सेवा के माध्यम से हो सकता है। जब व्यक्ति समाज में सकारात्मक योगदान देता है, तो उसमें संतोष और आत्म–मूल्य की भावना विकसित होती है। इसके विपरीत, यदि वह स्वयं तक सीमित रह जाता है और किसी प्रकार का योगदान नहीं कर पाता, तो उसमें ठहराव, निराशा और असंतोष की भावना उत्पन्न होती है।

इस प्रकार एरिक्सन का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य का संबंध उनके सामाजिक संबंधों और समाज में उनकी भूमिका से गहराई से जुड़ा हुआ है।

2. अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांतः मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मानव प्रेरणा को समझने का एक महत्वपूर्ण मॉडल है। इस सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति की आवश्यकताएँ पाँच स्तरों में व्यवस्थित होती हैंः

शारीरिक आवश्यकताएँः ये सबसे मूलभूत आवश्यकताएँ हैं जैसे भोजन, पानी, नींद और शारीरिक सुरक्षा। यदि ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं, तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रभावित होता है।

सुरक्षा आवश्यकताएँः इसमें आर्थिक सुरक्षा, नौकरी की स्थिरता, स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा शामिल है। आज के समय में आर्थिक अस्थिरता इस स्तर को सबसे अधिक प्रभावित करती है।

प्रेम और संबंधः इस स्तर पर व्यक्ति को परिवार, मित्रों और सामाजिक समूहों से जुड़ाव की आवश्यकता होती है। सामाजिक अलगाव इस आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालता है।

आत्मसम्मानः इसमें आत्म–सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और उपलब्धियों की मान्यता शामिल होती है। कार्यस्थल पर असफलता या सामाजिक उपेक्षा इस स्तर को प्रभावित करती है।

आत्म–साक्षात्कारः यह मैस्लो की उच्चतम आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार, यदि आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक असुरक्षा या भावनात्मक असंतुलन होता है, तो व्यक्ति इन आवश्यकताओं के उच्च स्तरों तक नहीं पहुँच पाता। इस प्रकार वयस्क जीवन

में सामाजिक–आर्थिक चुनौतियाँ न केवल बाहरी परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक प्रेरणा और आत्म–विकास की प्रक्रिया को भी बाधित करती हैं।

अतः उपरोक्त मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से स्पष्ट रूप से वयस्कों की मनो–सामाजिक जरूरतों और उनके अन्य मनोवैज्ञानिक पक्षों को भली–भांति समझा जा सकता है।

वयस्कों की सामाजिक–आर्थिक चुनौतियाँ

वर्तमान समय में वयस्क अनेक प्रकार की सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वैश्वीकरण, तकनीकी विकास, प्रतिस्पर्धा के चलते आपसी दूरियों ने वयस्क जीवन को अत्यंत जटिल और कठिन बना दिया है। ये चुनौतियाँ केवल आर्थिक या सामाजिक स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका गहरा प्रभाव वयस्कों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर भी प्रत्यक्षरूप से पड़ता है। इन चुनौतियों को चार प्रमुख वर्गों जैसे– आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी में समझा जा सकता है।

आर्थिक चुनौतियाँः आर्थिक चुनौतियाँ वयस्क जीवन की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। आज के समय में रोजगार का बाजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है, जिसके कारण बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गई है। शिक्षित होने के बावजूद वयस्कों को अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पाता है। परिणामस्वरूप व्यवहार में असंतुष्टि को प्रकट करता है। इसके साथ ही नौकरी की असुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय निरंतर बना रहता है। अस्थायी रोजगार, अनुबंध अधारित नौकरियों के कारण रोजगार की स्थिरता कम हो गई है, जिससे वयस्कों में मानसिक तनाव बढ रहा है। बढ़ती महंगाई भी आर्थिक दबाव को और अधिक बढ़ा देती है। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन होता जा रहा है। इसके अलावा, आय असमानता समाज में आर्थिक विभाजन को बढ़ावा देती है। कुछ वर्ग अत्यधिक धनी हो रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग आर्थिक संघर्ष का सामना कर रहे हैं। अतः इस तरह वयस्कों की आर्थिक चुनौतियों को समझा जा सकता है।

सामाजिक चुनौतियाँः सामाजिक जीवन में वयस्कों को अनेक जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ जैसे बच्चों की शिक्षा, वृद्ध माता–पिता की देखभाल और घरेलू दायित्व व्यक्ति पर मानसिक दबाव डालते हैं। वर्तमान के समाज में पीढ़ीगत अंतर भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। युवा और वयस्क पीढ़ी के विचारों, मूल्यों और जीवनशैली में अंतर के कारण पारिवारिक और सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है। इसके साथ ही सामाजिक तुलना और दबाव भी वयस्क मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अक्सर वयस्क अपनी तुलना दूसरों से करते हैं जो इस अवस्था में स्वाभाविक होती है, जिससे असंतोष, हीन भावना और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है।

मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँः सामाजिक और आर्थिक दबावों का सीधा प्रभाव वयस्क के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तनाव वर्तमान समय की सबसे गम्भीर समस्या बन चुकी है, जो कार्यस्थल, परिवार और आर्थिक जिम्मेदारियों से उत्पन्न होती है। चिंता भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण बढ़ती जा रही है, जबकि लगातार दबाव और असफलताओं के कारण अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त, लगातार असफलताओं, सामाजिक तुलना और आत्म–संदेह के कारण आत्म–सम्मान

में कमी आती है, जो व्यक्ति के आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है। इस प्रकार वयस्कों में मनोवैज्ञानिक चुनौतियों को देखा जा सकता है जो सचमुच गंभीर होती हैं।

तकनीकी/डिजिटल चुनौतियाँ: आधुनिक युग में तकनीक ने जीवन को सरल बनाया है, लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है, जहाँ निरंतर तुलना और प्रदर्शन की संस्कृति विकसित होती है। सूचना अधिभार के कारण व्यक्ति अत्यधिक जानकारी से भ्रमित हो जाता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। वयस्कों में डिजिटल लत भी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसमें वयस्क अत्यधिक समय मोबाइल और इंटरनेट पर व्यतीत करते हैं। इसके परिणामस्वरूप कार्य–जीवन असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत समय नकारात्मकरूप से प्रभावित होता है।

चुनौतियों का प्रभाव

वयस्क जीवन में उत्पन्न होने वाली सामाजिक–आर्थिक, मानसिक चुनौतियाँ केवल बाहरी परिस्थितियों को ही प्रभावित नहीं करतीं, बल्कि व्यक्ति के समग्र मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इन प्रभावों को विभिन्न स्तरों पर समझा जा सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: सतत तनाव, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक दबाव वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएँ निरंतर रूपसे बढ़ती जा रही हैं। लगातार मानसिक दबाव व्यक्ति की सोचने–समझने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और भावनात्मक संतुलन को कमजोर कर देता है। लंबे समय तक यह स्थिति रहने पर मानसिक थकान और भावनात्मक अस्थिरता के साथ–साथ अप्रत्यक्षरूप से वयस्कों को शारीरिक रूप से कमजोर बनाती जा रही हैं।

पारिवारिक संबंधों में तनाव: सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कार्यस्थल का दबाव और आर्थिक चिंताएँ वयस्कों को परिवार के साथ पर्याप्त समय और भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करने से रोकती हैं। इसके कारण पारिवारिक संवाद में कमी, वैवाहिक तनाव और पीढ़ीगत संघर्ष जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इससे परिवार की भावनात्मक एकता कमजोर होती है।

कार्य क्षमता में कमी: लगातार मानसिक तनाव और असंतुलित जीवनशैली के कारण व्यक्ति की कार्य दक्षता प्रभावित होती है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, निर्णय लेने में देरी और रचनात्मकता में कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रभावित होता है, बल्कि संगठनात्मक उत्पादकता भी घटती है।

सामाजिक अलगाव: अत्यधिक कार्यभार, डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग और मानसिक तनाव के कारण वर्तमान में वयस्क धीरे–धीरे सामाजिक गतिविधियों से दूर होने लगते हैं। धीरे–धीरे यह स्थिति सामाजिक अलगाव को जन्म देती है, जिसमें वयस्क मित्रों और समाज से निःसंदेह रूपसे कटने लगता है। इससे अकेलापन और भावनात्मक असुरक्षा की भावना और अधिक बढ़ जाती है।

जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न व्यवहारात्मक गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

जीवन संतुष्टि में गिरावट : इन सभी चुनौतियों का समग्र प्रभाव व्यक्ति की जीवन संतुष्टि पर पड़ता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन, सफलता और मानसिक शांति महसूस नहीं करता, तो उसमें निराशा और असंतोष की भावना बढ़ जाती है। इससे उसका आत्म–मूल्यांकन नकारात्मक हो जाता है और जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है और कभी–कभी तो वयस्क आत्महत्या कैसे कृत्य से अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का प्रभाव बहुआयामी और गहरा होता है, जो वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, कार्यक्षमता, सामाजिक संबंधों और समग्र जीवन संतुष्टि को नकारात्मक रूपसे प्रभावित करता है।

समाधान हेतु महत्त्वपूर्ण रणनीतियाँ

यह प्राकृतिक रूप से सही है कि अगर समस्या है तो प्रकृति में समाधान भी हैं ही। कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं होती है। इसमें शिक्षा और जागरूकता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस तरह वयस्कों के जीवन में उत्पन्न सामाजिक–आर्थिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ बहुआयामी होती हैं, अतः इनके समाधान भी बहुस्तरीय दृष्टिकोण से किए जाने आवश्यक हैं। केवल व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं होते, बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और नीतिगत हस्तक्षेप भी आवश्यक है। निम्न रणनीतियों द्वारा इसे समझा जा सकता है।

व्यक्तिगत स्तर पर समाधानः वयस्क अपने मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए अनेक आत्म–प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं।

- योग, ध्यान और माइंडफुलनेस मानसिक तनाव को कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी हैं। ये तकनीकें व्यक्ति को वर्तमान क्षण में रहने और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाने में सहायता करती हैं।
- समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संतुलित ढंग से पूरा कर सकता है। इससे कार्य–जीवन संतुलन बेहतर होता है।
- सकारात्मक सोच व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता को बढ़ाती है और कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है।
- भावनात्मक नियंत्रण व्यक्ति को क्रोध, चिंता और तनाव जैसी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे मानसिक स्थिरता बनी रहती है।

सामाजिक स्तर पर समाधानः सामाजिक समर्थन प्रणाली व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- पारिवारिक सहयोग व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है और तनावपूर्ण परिस्थितियों में सहारा देता है।
- सामाजिक समर्थन प्रणाली जैसे मित्र, सहकर्मी और समुदाय व्यक्ति को मानसिक मजबूती प्रदान

करते हैं।

- सामुदायिक सहभागिता व्यक्ति को समाज से जोड़ती है और उसमें अपनापन तथा सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। इससे अकेलेपन की भावना कम होती है।

शैक्षिक एवं कौशल विकास आधारित समाधानः शिक्षा और कौशल विकास वयस्क जीवन की चुनौतियों को कम करने में अत्यंत प्रभावी साधन हैं।

- वयस्क शिक्षा कार्यक्रम उन व्यक्तियों को शिक्षा और ज्ञान प्रदान करते हैं जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
- व्यक्ति को रोजगार योग्य बनाते हैं और रोजगार के नए अवसर प्रदान करते हैं, जिससे आर्थिक असुरक्षा कम होती है।
- डिजिटल साक्षरता आज के तकनीकी युग में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्ति को डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन संसाधनों का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करना सिखाती है।

मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपः मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए पेशेवर सहायता अत्यंत आवश्यक है।

- परामर्श सेवाएँ व्यक्ति को अपनी समस्याओं को समझने और समाधान खोजने में सहायता करती हैं।
- मनोचिकित्सा गंभीर मानसिक समस्याओं जैसे अवसाद और चिंता के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- जागरूकता कार्यक्रम समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं और कलंक को कम करते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वयस्कों की चुनौतियों के समाधान हेतु व्यक्तिगत प्रयासों के साथ–साथ सामाजिक सहयोग, शैक्षिक सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वित उपयोग आवश्यक है। यह समग्र दृष्टिकोण व्यक्ति को एक संतुलित, उत्पादक और संतुष्ट जीवन जीने में सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 के परिप्रेक्ष्य में चर्चा

वयस्क मनोविज्ञान का अध्ययन केवल व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं और मानसिक प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और नीतिगत संदर्भों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में वयस्कों के समक्ष बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, बढ़ती महंगाई, पारिवारिक दायित्व, सामाजिक दबाव, तकनीकी परिवर्तन और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ प्रमुख चुनौतियों के रूप में उभर रही हैं। इन चुनौतियों का प्रभाव न केवल वयस्क के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि उसकी कार्यक्षमता, सामाजिक संबंधों और जीवन संतुष्टि को भी प्रभावित करता है। इसलिए इन समस्याओं को केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक और नीतिगत दृष्टिकोण से

समझने की आवश्यकता है।

इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 वयस्क शिक्षा और आजीवन सीखने को विशेष महत्व प्रदान करती है। यह नीति इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा केवल बाल्यावस्था या युवावस्था तक सीमित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवनपर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। तेजी से बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में वयस्कों को निरंतर नए ज्ञान, कौशल और दक्षताओं की आवश्यकता होती है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 वयस्कों को केवल शिक्षार्थी नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय और सतत विकसित होने वाले मानव संसाधन के रूप में देखती है। नीति में वयस्क शिक्षा एवं आजीवन अधिगम मिशन का विशेष उल्लेख किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को शिक्षा और सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि समाज का प्रत्येक वयस्क व्यक्ति पढ़ने–लिखने और गणनात्मक दक्षताओं से सशक्त हो सके। साक्षरता केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक भागीदारी को भी बढ़ाती है। नीति में सामुदायिक शिक्षा केंद्रों और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है। ये केंद्र वयस्कों को सीखने, कौशल विकास और सामाजिक सहभागिता के अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, जिससे व्यक्ति बदलते रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सके। यह दृष्टिकोण बेरोजगारी और नौकरी की असुरक्षा जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वयस्क मनोविज्ञान की समस्याएँ केवल व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक–आर्थिक संरचनाओं और नीतिगत व्यवस्थाओं से भी प्रभावित होती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 इन चुनौतियों के समाधान के लिए शिक्षा, कौशल विकास, साक्षरता और आजीवन अधिगम को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत करती है। अतः वयस्कों के समग्र विकास और मानसिक कल्याण के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के साथ–साथ प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप और सामाजिक सहयोग भी समान रूप से आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

वयस्कों का मनोविज्ञान आधुनिक समाज के अध्ययन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन–चक्र में उसकी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करता है। वयस्क अवस्था में व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया से गुजरता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन करता है। इस दौरान उत्पन्न होने वाली सामाजिक–आर्थिक चुनौतियाँ जैसे बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक दबाव, सामाजिक तुलना, तकनीकी परिवर्तन और कार्य–जीवन असंतुलन, उसके मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इन चुनौतियों के परिणामस्वरूप तनाव, चिंता, अवसाद, आत्म–सम्मान में कमी और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो व्यक्ति की कार्यक्षमता और जीवन संतुष्टि को प्रभावित करती हैं। इसलिए इन समस्याओं का समाधान केवल व्यक्तिगत प्रयासों तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए सामाजिक समर्थन, शैक्षिक सशक्तिकरण तथा नीतिगत

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 24

हस्तक्षेप आवश्यक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 वयस्क शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और आजीवन सीखने को प्रोत्साहित करती है। यह नीति वयस्कों को केवल शिक्षार्थी नहीं, बल्कि निरंतर विकसित होने वाले सक्षम नागरिक के रूप में देखती है, जो समाज और अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दे सकते हैं। इन सभी उपायों – व्यक्तिगत, सामाजिक और नीतिगत को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो वयस्क जीवन में मानसिक संतुलन, सामाजिक समरसता और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे वयस्क अधिक संतुलित, उत्पादक, आत्मनिर्भर और संतुष्ट जीवन जीने में सक्षम होंगे।

संदर्भ

1. Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis.
2. Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality.
3. Knowles, M. (1980). The Modern Practice of Adult Education.
4. Ministry of Education (2020). National Education Policy 2020, Government of India.
5. Sandip Kumar, & Ashok Kumar. (2025). Indian Knowledge System in Contemporary System: Pathway to Lifelong and Sustainable Learning. The Asian Thinker: A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Science and Humanities, 7(4), Special Issue (October–December 2025).
6. कुमार (2025) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोवज्ञानिक की भूमिका, संस्कृत मंजरी, – विद्वत समीक्षित एवं संदर्भित त्रैमासिक शोध पत्रिका, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार, अंक 292025 आई एसएस एन – 2278–8360.

❍❍❍❍❍

"हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांतिप्रिय हैं, और रहें। हमारा साम्राज्य, हमारी फतह दूसरे प्रकार की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वह लोहे की हों, या सोने की भी क्यों न हो, कभी बांधने की कोशिश नहीं की। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे की जंजीर से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है और वह बंधन धर्म का है, संस्कृति का है और ज्ञान का है।"

– डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 25

संस्कृत साहित्य में निहित व्यावहारिक ज्ञानः श्रीमद्भगवद्गीता के संदर्भ में

– अनिता जोशी
– माया जोशी

भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत संस्कृत साहित्य में आत्मा व परमात्मा, जीव व जगत का वर्णन करते हुए इसके माध्यम से धर्म, ज्ञान व कर्म के द्वारा समाज को नैतिकता की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में भी संस्कृत भाषा के वृहद एवं महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए संस्कृत को मुख्य धारा में लाने का विचार व्यक्त किया गया है। विभिन्न विभागों के आदर्श वाक्य संस्कृत साहित्य से ही लिये गये हैं। संस्कृत साहित्य के ही एक ग्रंथ श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेशों के रूप में प्रदत्त व्यावहारिक ज्ञान को 18 अध्यायों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें सफलता व असफलता को समभाव से ग्रहण करने, दम्भ, द्वेष, अभिमान, क्रोध को त्यागने, इंद्रियों तथा मन को नियंत्रित करने, संतुलित आहार व विहार अपनाने तथा भौतिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु योगाभ्यास करने पर बल दिया गया है। योग के अभ्यास हेतु उपयुक्त आसन व विधि का वर्णन भी इस ग्रंथ में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त सात्विक, राजसी व तामसिक इन तीन प्रवृत्तियों के आधार पर व्यक्ति, यज्ञ, तप, दान, ज्ञान, कर्म व कर्ता के भी तीन प्रकार बताए गए हैं। पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण में रत वर्तमान भारतीय समाज के लिए श्रीमद्भगवद्गीता का व्यवहारिक ज्ञान भावी पीढ़ी की चेतना जागृत करने में सर्वथा सक्षम है। यह संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करने वाला संस्कृत साहित्य का सार्वभौमिक ग्रंथ है।

मुख्य शब्दः संस्कृत साहित्य, श्रीमद्भगवदगीता, व्यावहारिक ज्ञान, योगाभ्यास

संस्कृत साहित्य में निहित भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय है। इसके माध्यम से सांसारिक प्राणियों को धर्म, ज्ञान व कर्म के माध्यम से नैतिकता की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया गया है। संस्कृत भाषा में हमारी संस्कृति के मूल तत्व निहित हैं, जिन्हें संस्कृत भाषा की पाठ्यपुस्तकों में सुभाषितानि के रूप में भावी पीढ़ी को मानव मूल्यों को अपनाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से संकलित किया गया है। ये श्लोक विभिन्न ग्रंथों से उद्धृत किए गए हैं। परिहार एवं चौहान (2024) के अनुसार प्राचीन ज्ञान परंपराएं मानवता को प्रोत्साहित करती रही हैं तथा इनका उद्देश्य मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में भी कहा गया है कि संस्कृत भाषा के वृहद एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं के साहित्य, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को मुख्य धारा में लाया जाएगा। संस्कृत साहित्य इतना विशद है कि उसमें प्रत्येक कार्यक्षेत्र को वर्णित किया गया है। विभिन्न विभागों के आदर्श वाक्य संस्कृत में होना, जैसे– भारत सरकार का आदर्श वाक्य – सत्यमेव जयते, लोकसभा – धर्मचक्र प्रवर्तनाय, उच्चतम न्यायालय – यतो धर्मस्ततो जय, आकाशवाणी – सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय, दूरदर्शन – सत्यम् शिवम् सुंदरम्, थलसेना – सेवा अस्माकम धर्मः, वायु सेना – नभः स्पृशं दीप्तम्, जल सेना – शं नो वरुणः, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान – शरीरमाद्यम् खलु धर्म साधनम्, इस भाषा की महत्ता को इंगित करते हैं।

शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न विभागों के आदर्श वाक्य भी संस्कृत में ही हैं जैसे – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद – गुरुर्गुरुतमो धाम, राष्ट्रीय

शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद – विद्यया अमृतमश्नुते, केंद्रीय विद्यालय – तत् त्वम् पूषन अपावृणु, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड – असतो मा सद्गमय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद – योगः कर्मसु कौशलम्। ये सभी संस्कृत साहित्य की गरिमा के प्रतीक हैं। माझी (2024) के अनुसार संरक्षण की चुनौतियों के बावजूद संस्कृत साहित्य ज्ञान का विपुल भंडार है जो विद्वानों, कलाकारों और साधकों को प्रेरित करता है। संस्कृत साहित्य का ही एक ग्रंथ है – श्रीमद्भगवदगीता, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का अद्वितीय स्वरूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में वर्णित किया गया है। प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य संस्कृत साहित्य के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में निहित भारतीय ज्ञान परंपरा का विश्लेषण करना है, जिसके लिये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद्भगवद्गीता को मुख्य ग्रंथ के रूप में लिया गया है।

श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय ज्ञान परंपरा का ऐसा साहित्यिक प्रमाण है, जिसके 18 अध्यायों में श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध स्थल में मोहबंधन से मुक्ति हेतु प्रदत्त ज्ञान संकलित है। यह ज्ञान मानवता के उत्थान हेतु आवश्यक है। श्रीमद्भगवद्गीता आध्यात्मिक साक्षात्कार हेतु ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग का मार्ग बताते हुए अस्तित्व सम्बंधित दुविधाओं और नैतिक चिंताओं को संबोधित करती है (माझी, 2024)।

गीता का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' व्यक्ति को कर्म की ओर आसक्त करता है। श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन के माध्यम से संदेश दिया गया है कि व्यक्ति का कर्तव्य करने का अधिकार है, फल प्राप्ति का अधिकार नहीं है। व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर अग्रसर करना भारतीय ज्ञान परंपरा की अद्वितीय विशेषता है। जो व्यक्ति कर्तव्य की बजाय अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक सजग होता है, वह स्वार्थी व्यक्ति होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझकर दायित्वों का निर्वहन करता है, वह व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति होता है और आदर्श समाज की स्थापना में सहायक होता है। ऐसा व्यक्ति कभी आलसी नहीं हो सकता। वह अपने, समाज व राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। कर्तव्यरत व्यक्ति को या तो सफलता प्राप्त होती है या फिर असफलता। सफलता व असफलता जीवन के दो अनिवार्य पहलू हैं। असफलता को भी यदि सकारात्मक रूप से लिया जाए तो वह सीखने का अवसर प्रदान करती है, दूसरी ओर असफलता को नकारात्मक रूप से ग्रहण करने पर वह तनाव व द्वंद् पैदा करती है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी जीवन में सफलता व असफलता दोनों को समान भाव से ग्रहण करने का संदेश अध्याय 2 के श्लोक संख्या 48 में दिया गया है।

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥48॥

इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आसक्ति को त्याग कर समभाव होकर कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं। उनके अनुसार सफलता और असफलता में समभाव होने की क्षमता ही योग कहलाती है। यह क्षमता ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। व्यावहारिक जीवन में यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समाज में सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। सफलता व्यक्ति में दंभ, दर्प व अभियान का भाव उत्पन्न कर सकती है, जबकि असफलता क्रोध व तनाव उत्पन्न कर सुखमय जीवन जीने में बाधा उत्पन्न करती है। इन भावों के वशीभूत होकर ही मनुष्य दुर्व्यवहार की ओर प्रवृत्त होता है। दम्भ, दर्प, क्रोध, अभिमान, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति की विशेषताएं मानी गई हैं। श्रीमद्भगवदगीता के अध्याय 16 में यह भाव निम्न श्लोक के माध्यम से व्यक्त किया गया है–

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 27

दम्भो दर्पो भिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥4॥

ऐसे लोग अपनी विद्या व संपत्ति का घमंड करते हैं, सम्मान के योग्य न होने के बावजूद अपना सम्मान चाहते हैं, छोटी–छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। अतः इन दुर्गुणों से बचने का प्रयास किया जाना चाहिये। क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण माना गया है। क्रोधी व्यक्ति को भले बुरे की समझ नहीं रहती। श्रीमद्भगवदगीता के अध्याय 2 का निम्न श्लोक यही भाव व्यक्त करता है–

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः।

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥63॥

अर्थात क्रोध मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, जिससे मनुष्य को उपयुक्त और अनुपयुक्त का भेद ज्ञात नहीं हो पाता और वह बिना सोचे समझे क्रोध के वशीभूत होकर ऐसे कार्य करता है, जो उसके विनाश का कारण बन जाता है। क्रोधी व्यक्ति हिंसा की स्थिति तक भी पहुंच जाता है। क्रोध की इस अनियंत्रित स्थिति के कारण ही आज समाज में हिंसा की प्रवृत्ति व्याप्त होती जा रही है। छोटी–छोटी अपेक्षाओं के पूरा न होने पर क्रोधित होना युवा पीढ़ी के बीच आज सामान्य स्थिति है, जिसके परिणामस्वरुप कभी–कभी हिंसात्मक स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इस संदर्भ में श्रीमद्भगवदगीता समाज को क्रोध की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने हेतु प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त काम और लोभ जैसे विकार भी समाज के विकास में अत्यंत बाधक हैं। श्रीमद्भगवदगीता के अध्याय 16 के 21वें श्लोक में श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को काम, क्रोध और लोभ इन तीनों विकारों को अधोगामी मानते हुए इन्हें त्यागने का उपदेश दिया गया है।

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामःक्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥21॥

श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह संदेश वर्तमान समाज में अत्यंत प्रासंगिक है। इस प्रकार श्रीमद्भगवदगीता व्यक्ति को दुष्प्रवृत्तियों को त्याग कर सत्कार्यों की ओर अग्रसर करने हेतु प्रेरित करती है। काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर ही मनुष्य उन कृत्यों को करने पर विवश हो जाता है, जिनके विषय में वह जानता भी है कि एसे कार्य समाज में निम्नता की ओर ले जाने वाले हैं, परंतु इंद्रियों की क्षणिक तुष्टि को ही मनुष्य आनंद मानकर अपने व्यक्तित्व को कमजोर कर लेता है। श्रीमद्भगवदगीता का ज्ञान व्यक्ति को इंद्रियों की वशीभूत करने का ज्ञान प्रदान करता है। जिसने विचलनशील इंद्रियों को वश में कर लिया हो, ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति श्रद्धा के माध्यम से ही हो सकती है। अध्याय 4 का निम्न श्लोक यही भाव व्यक्त करता है।

श्रद्धावान्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥39॥

अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो हमेशा तत्पर रहता है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति हेतु श्रद्धा व विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। अभिमानी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। काम, क्रोध और लोभ से बचने हेतु इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक माना गया है। ज्ञान के बिना इंद्रियों की संतुष्टि में लगा मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सारे सुख उपलब्ध होने पर भी मन में यदि नकारात्मक विचार भरे हों, तो वे मनुष्य को दुखी बनाये रखते हैं। मन की चंचलता व्यक्ति को स्थिर नहीं होने देती, वह किसी भी कार्य में निरत नहीं रह पाता। अतः जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है जो लक्ष्य

प्राप्त करने में सहायता करता है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा और लक्ष्य प्राप्त करने मे बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए मन को वश में रखना आवश्यक माना गया है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो ऐसा धैर्यशाली व्यक्ति जीवन की विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने की कला सीख लेता है। स्थिर मन व्यक्ति को दुविधा जनक स्थिति से उभरने में सहायता करता है। श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय–6 के निम्न श्लोक के माध्यम से यही भाव व्यक्त किया गया हैः

बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः।

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ 6॥

भारतीय परम्परा में आहार विहार का संतुलन भी आवश्यक माना गया है। ब्रहम मुहुर्त में जागना, समय पर सोना, अल्पाहारी होना, सदैव कर्म में लगे रहना, सद्व्यवहार करना सत्पुरुष के लक्षण माने गये हैं। गीता के अध्याय–6 के निम्न श्लोक में भी कहा गया है कि अधिक खाने वाले अथवा कम खाने वाले, अधिक सोने वाले अथवा कम सोने वाले का योग सिद्ध नहीं होता जो खाने, सोने तथा जागने, आहार तथा विहार व कर्म करने की आदतों में नियमित होता है, ऐसा व्यक्ति योगाभ्यास द्वारा समस्त कष्टों को नष्ट कर सकता है।

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥17॥

प्राचीन ऋषि मुनि योग के माध्यम से अपनी शारीरिक आवश्यकताओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे। श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय में भी शरीर पर नियंत्रण रखते हुए योग की उपयुक्त शारीरिक स्थिति का वर्णन किया गया है। योग की उपयुक्त शारीरिक स्थिति को महत्वपूर्ण मानते हुए श्लोक संख्या 13 में कहा गया है कि योगाभ्यास करने वाले को शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा–सीधा रखते हुए नाक के अगले सिरे पर दृष्टि जमानी चाहिए।

समम् कायशिरोग्रीवम् धारयन्नचलम स्थिरः।

सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रम् स्वम् दिशश्चानवलोकयन् ॥13॥

इसी प्रकार अध्याय 17 के 14वें, 15वें तथा 16वें श्लोक में शारीरिक, वाणिक व मानसिक तप का वर्णन किया गया है। देवता, ब्राह्मण, गुरु तथा ज्ञानीजनों का पूजन एवं पवित्रता सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। शारीरिक, वाणिक व मानसिक तप का पालन करने वाले व्यक्ति ही समाज में सम्मान के हकदार होते हैं। वे स्वयम संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतोष प्रदान करते हैं। सत्य, प्रिय, हितकारी तथा अन्य लोगों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और स्वाध्याय का अभ्यास करना निश्चित ही वाणी का तप है। मन की संतुष्टि, सौम्यता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि यह मन की तपस्या है। अर्थात श्रीमद्भगवद्गीता व्यक्ति को यह संदेश देती है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिये कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो जाये। साथ ही मन को छल कपट से मुक्त कर सबके हित के विषय में सोचना चाहिये।

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम शौचमार्जवम्।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम् तप उच्यते।।14॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहिंत च यत्।

स्वाध्यायाभ्यसनं चौव वाङ्मयं तप उच्यते ॥15॥

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 29

मनःप्रसादःसौम्यत्वम मौनम्मात्मविनिग्रह

भावसंशुद्धिरितयेत्तपो मानसमुच्यते ॥ 16 ॥

भारतीय परम्परा में तीन प्रकार के व्यक्ति माने गये हैं – सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। ये सभी व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार भोजन, यज्ञ, तप व दान के भागी बनते हैं। इनमें सतोगुणी व्यक्तियों को ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार सात्विक भोजन, सात्विक यज्ञ, सात्विक तपस्या तथा सात्विक दान को ही उपयुक्त मानते हुए विभिन्न धर्मग्रंथों के माध्यम से इन्हें अपनाने हेतु प्रेरित किया गया है। श्रीमदभागवद गीता के 17वें अध्याय में सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों की अपने–अपने गुणों के अनुसार विशेष प्रकार की श्रद्धा बताई गई है। सतोगुणी व्यक्ति देवता को पूजते हैं, रजोगुणी व्यक्ति यक्ष व राक्षसों को पूजते हैं तथा तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। भोजन, यज्ञ, तपस्या तथा दान भी तीन प्रकार के बताए गए हैं। 17वें अध्याय में उल्लिखित श्लोक संख्या 8 में सात्विक भोजन को वर्णित करते हुए कहा गया है–

आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्द्धनाः।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहारः सात्त्विकप्रियाः ॥8 ॥

अर्थात आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त, चिकने पदार्थ, हृदय को भाने वाले पदार्थ सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं (इसीलिये ये आहार सात्विक कहलाते हैं)। इसी प्रकार श्लोक संख्या 9 एवम 10 में क्रमशः राजसी तथा तामसी भोजन को वर्णित करते हुए कहा गया है कि गरम, चटपटे, शुष्क, कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा दाहकारक दुख, शोक, रोग उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। इसी प्रकार अधपका, रसरहित, दुर्गंधयुक्त बासी उच्छिष्ट तथा अपवित्र भोजन तामसिक व्यक्ति को प्रिय होता है (इसीलिये ये आहार राजसी एवम तामसी कहलाते हैं)।

अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते।

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥11 ॥

इसी प्रकार अध्याय 17 के उपरोक्त श्लोक में सात्विक यज्ञ को वर्णित किया गया है। बिना फल की इच्छा के किया गया यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है, जबकि दम्भ अथवा फल के उद्देश्य से किया गया यज्ञ राजसी तथा बिना श्रद्धा के किया गया यज्ञ तामसी कहलाता है (श्लोक संख्या 12 व 13)।

इसी प्रकार किसी वांछित व्यक्ति को सामने देख कर जब बिना किसी प्रतिकार की आशा से कर्तव्य समझकर व्यक्ति द्वारा दान दिया जाए, तो यह दान सात्विक कहलाता है। श्रीमद्भगवद्गीता में इसी प्रकार के दान को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह दान योग्य व्यक्ति को उपयुक्त समय पर दिया गया दान होता है। दान के दो अन्य प्रकार भी बताए गए हैं – राजसी दान व तामसिक दान। जो दान प्रतिकार की भावना से अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह राजसी दान माना जाता है तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है वह तामसिक दान कहलाता है (श्लोक संख्या 21 एवम 22)। इस प्रकार अध्याय 17 व्यक्ति को निष्काम भाव से परम श्रद्धा के साथ कार्य करने की ओर प्रवृत्त करता है।

दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥20 ॥

श्रीमद्भगवद्गीता के 18वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म व कर्ता के भी सात्विक, राजसी व तामसिक, ये तीन भेद बताये गये हैं। जिस ज्ञान से प्राणी सम्पूर्ण जीव जगत में

एक आध्यात्मिक प्रकृति को देखता है, वह सात्विक ज्ञान कहलाता है। निम्न श्लोक में सात्विक ज्ञान का वर्णन किया गया है।

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् ॥20॥

इसके विपरीत जिस ज्ञान से प्राणी विभिन्न शरीरों मे भिन्न भिन्न जीव देखता है, वह राजसी ज्ञान कहलाता है तथा जिस ज्ञान से मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान कर उसमें आसक्त रहता है, वह तामसी ज्ञान कहलाता है (श्लोक संख्या 21 व 22)।

इसी प्रकार कर्म के भी तीन भेद बताए गए हैं – सात्विक कर्म, राजसी कर्म तथा तामसिक कर्म। इनमें से सात्विक कर्म को महत्व दिया गया है क्योंकि यह निष्काम भाव से किया जाता है। कर्म के पश्चात फल प्राप्ति की चाहत व्यक्ति को नहीं रहती। इस प्रकार का कर्म व्यक्ति को कर्तव्य निष्ठ बनाता है।

नियतं सग्ङरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।

अफलप्रेप्सुना कर्म यतत्सात्त्विकमुच्यते ॥23॥

इसके विपरीत जिस कर्म के साथ इच्छा जुड़ी होती है और यह कार्य मैंने संपादित किया ऐसा अहम भाव भी जुड़ा होता है, वह राजसी कर्म कहलाता है यद्यपि इस कर्म में दूसरे के अहित का भाव नहीं रहता है। तामसिक कर्म परिणाम को विचारे बिना हिंसा, हानि के लिए मोहपूर्वक व अज्ञानपूर्वक पूर्वक किया जाता है। (श्लोक संख्या – 24 व 25)।

श्रीमद्भगवदगीता के अनुसार कर्ता भी तीन प्रकार के बताए गए हैं – सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता और तामसी कर्ता। सात्विक कार्यों को संपादित करने वाला, अहंकार से रहित, उत्साह पूर्ण, कर्तव्य निष्ठ, सफलता व असफलता के प्रति समान भाव रखने वाला कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है। अध्याय 18 के निम्न श्लोक में सात्विक कर्ता का वर्णन किया गया है–

मुक्तसग्ङो नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।

सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारकर्ता सात्त्विक उच्यते ॥26॥

कर्म के फल को चाहने वाला, लोभी, ईर्ष्यालु, अपवित्र व सुख–दुख में विचलित होने वाला कर्ता राजसी कर्ता कहलाता है तथा शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने वाला, भौतिकवादी, हठी, कपटी, दूसरों का अपमान करने वाला आलसी और दीर्घ सूत्री तामसी कहलाता है (श्लोक संख्या 27 व 28)।

श्रीमद्भगवद्गीता के इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अर्जुन का सारा संशय दूर हो गया था। वर्तमान समाज में भी जिस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां व्याप्त हो गई हैं, वहां गीता में निहित यह ज्ञान परंपरा लोगों में चेतना जागृत करने में सक्षम है। पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करते हुए मनुष्य नाशवान शरीर को ही सब कुछ मानकर इंद्रियों की तुष्टि में लगा रहता है। आम जनमानस संस्कृत को पंडिताई हेतु आवश्यक भाषा मान लेता है। जबकि संस्कृत साहित्य ज्ञान का विपुल भंडार है। इस भाषा के ग्रंथों में अधिकांश ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान (परा ज्ञान) से युक्त हैं। लौकिक ज्ञान (अपरा ज्ञान) व्यक्ति को माया, मोह के बंधनों से युक्त रखता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान (परा ज्ञान) जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति को मार्गदर्शन प्रदान करता है (जोशी एवम जोशी, 2021)। इन ग्रंथों की उपादेयता को इस बात से समझा जा सकता है कि श्रीमद्भगवद्गीता का अंग्रेजी के अतिरिक्त 500 से भी अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है (शतपथी एवम मुनैयन, 2008)। गीता का सर्वप्रथम अनुवाद वारेन हेस्टिंग्स की विशेष संस्तुति पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लंदन में किया गया था (आनंद, 2024)। इसमें दिया

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 31

गया ज्ञान आत्मानुभूति का मार्ग प्रशस्त करता है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के मन में उत्पन्न संशय का निवारण कर उसे आत्मबल प्रदान करता है ।

अतः कहा जा सकता है कि श्रीमद्भगवद्गीता सम्पूर्ण विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करने वाला सार्वभौमिक ग्रंथ है। आज के भौतिकवादी युग में सामान्य जनमानस श्रीमद्भगवद्गीता के जीवन यापन में उपयोगी ज्ञान से अछूता है। डिजिटल युग में जीवनयापन करने वाली वर्तमान पीढ़ी इन बातों को यदि आत्मसात कर ले तो तनाव, चिंता, भौतिक उपलब्धियों की कामना से मुक्त होकर उन जीवन मूल्यों को धारण करने में समर्थ होगी जो जीवनयापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे – काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त रहना, सफलता के साथ ही असफलता को भी सकारात्मक रूप से स्वीकार करना, फल की इच्छा के बिना कर्मरत रहना, संतुलित जीवनचर्या को अपनाना, इंद्रियों को वश में रखना आदि। अतः पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण में रत वर्तमान भारतीय समाज के प्रत्येक जनमानस तक श्रीमद्भगवद्गीता का व्यावहारिक ज्ञान औपचारिक, अनौपचारिक अथवा गैर औपचारिक साधनों के माध्यम से पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ

1. आनंद, तथागत (2024), द भगवद्गीता कास्ट इट्स स्पेल आन द वेस्ट, वेदांत सोसाइटी न्यूयार्क।
2. जोशी, ए एवं जोशी, एस (2021), सार्वभौमिक शिक्षा दर्शनः श्रीमद्भगवद्गीता दर्शन, दृष्टिकोण, वर्ष 13, अंक 1, जनवरी–फरवरी।
3. माझी, एल, (2024), एक्सप्लोरिंग द सिगनिफिकेंस ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन सेपिंग ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम, पार्टनर्स यूनिवर्सल इंटरनेशनल इनोवेशन जरनल, वॉल्यूम 2, इश्यु 3, मई–जून 2024, www-puiij-com।
4. परिहार, एस एवं चौहान, पी (2024), भारतीय ज्ञान परंपरा और इतिहास, इंटरनेशनल जनरल ऑफ एनहैंस्ड रिसर्च इन एजुकेशनल डेवलपमेंट, वॉल्यूम 12, इश्यु 1, जनवरी–फरवरी।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
6. स्वामी, पी (1990), श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, मुंबई।
7. शतपथी, वी एवम मुनैयन, बी (2008), द नोलेज ऑफ सेल्फ फ्रोम द्भगवद्गीता एंड इट्स सिगनिफिकेंस फोर ह्युमन कैपिटल डेवलपमेंट, वॉल्यूम 4, इश्यु 10, एसियन सोशियल साइंस, स्रोत–www-ccsenet-org-journal-html
8. श्रीमद्भगवद्गीता (2006), गीता प्रेस गोरखपुर ।

○○○○○

"भारत एक अद्भुत देश है, जहां व्यक्ति इसलिए लोकप्रिय नहीं होता कि उसके हाथ में शक्ति है, बल्कि वह पद छोड़ दे तो लोकप्रिय होता है।"

– नेताजी सुभाष चंद्र बोस

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 32

उल्लास और सभी के लिए प्रौढ़ और आजीवन शिक्षा

— सौरभ मिश्र

"उल्लास" एक परिचय :

"उल्लास" शब्द का उपयोग कई अलग–अलग संदर्भों में किया जाता है। यहाँ "उल्लास" का उल्लेख एक सरकारी योजना के रुप में किया गया है। जिसे अंग्रेजी में ULLAS कहा गया है उसका पूरा नाम Understanding of Lifelong Learning for All in Society (अन्डरस्डैंडिंग ऑफ लाइफलांग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाईटी) है। हिन्दी में इसे 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' कहा जाता है। यह सन् 2022–2027 के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरु की गयी एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। जिसका लक्ष्य 15 और उससे अधिक आयु वर्ग के उन व्यक्तियों को साक्षर बनाना है जिन्हें किसी भी कारणवश औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। इतना ही नहीं साक्षरता के तहत लाभार्थियों के शिक्षण को केवल पढ़ने–लिखने एवं अंक ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें 21वीं सदी के हिसाब से आवश्यक जीवन कौशल भी सिखाया जाना है। इसका व्यापक लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को साक्षर और कुशल नागरिक बनाना है तथा सन् 2030 तक शत्–प्रतिशत साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

"उल्लास" शब्द की उत्पत्ति

"उल्लास" शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। "उल्लास" का सन्धिविच्छेद "उद्+लास" है।

"उद्" एक उपसर्ग है जिसका अर्थ "ऊपर", "बाहर" अथवा "तेज" होता है। "लास" का अर्थ "चमक" या "खेलना" होता है। इस तरह "उल्लास" का एक शाब्दिक अर्थ है "बाहर की ओर चमकना" या "ऊपर की ओर उठना"। इसी से यह शब्द आनन्द, प्रसन्नता और खुशी जैसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। "उल्लास" एक तत्सम शब्द है जिसे संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिन्दी में लिया गया है।

"दिनेश प्रसाद सकलानी, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए 1 अप्रैल 2022 से भारत सरकार द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (उल्लास) का प्रारम्भ किया गया है जिसमें प्रौढ़ शिक्षा के सभी पक्ष शामिल हैं।"

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के दस्तावेजों में यह उल्लिखित है कि, सन् 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में निरक्षरों की कुल संख्या 25.76 करोड़ है जिसमें पुरुष 9.08 करोड़ एवं महिला 16.68 करोड़ शामिल हैं। सन् 2009–10 से सन् 2017–18 के दौरान साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत साक्षर के रुप में प्रमाणित व्यक्तियों की 7.64 करोड़ की प्रगति को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया गया कि, वर्तमान में भारत में लगभग 18.12 करोड़ व्यस्क अभी–भी निरक्षर हैं।

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 33

"उल्लास" के घटक :

"उल्लास" के अन्तर्गत पाँच कार्यक्रम आते हैं –

1. **मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता**– इसमें 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के उन व्यस्कों को पढ़ना, लिखना व अंकज्ञान के बुनियादी कौशल को सिखाना शामिल है जिन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिला।
2. **महत्वपूर्ण जीवन कौशल**– यह वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, कानूनी साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल, बाल देखभाल और परिवार कल्याण जैसे महत्त्वपूर्ण कौशल प्रदान करता है।
3. **बुनियादी शिक्षा**– यह उन लोगों को प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक शिक्षा के स्तर के बराबर ज्ञान देता है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं।
4. **व्यावसायिक कौशल का विकास**– इस घटक का उद्देश्य नए साक्षर लोगों को स्थायी रोजगार पाने में मदद करने के लिए व्यावसायिक कौशल सिखाना है।
5. **सतत शिक्षा**– इसमें कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेलकूद और मनोरंजन जैसे विषयों में आजीवन सीखने के अवसर शामिल हैं, ताकि व्यक्ति लगातार अपना विकास कर सकें।

"उल्लास" की प्रगति :

"उल्लास" एक मोबाईल एप्प के माध्यम से भी भारत सरकार द्वारा प्रचारित–प्रसारित किया गया है जिसे 29 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। "उल्लास" नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में साक्षरता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस योजना से पूरे देशभर से लोग FLNAT परीक्षा में शामिल हुए जिसका पूरा नाम Foundation Literacy and Numeracy Assessment Test है जिसे हिन्दी में बुनियादी साक्षरता और अंकज्ञान मूल्यांकन परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा से अब तक 77 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं।

FLNAT परीक्षा का उद्देश्य :

1. सभी शिक्षार्थियों को तीसरी कक्षा के अंत तक आवश्यक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल हासिल कराना है ताकि, शिक्षार्थियों के पढ़ने, लिखने और अंकज्ञान की दक्षता का मूल्यांकन हो सके।
2. यह परीक्षा शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमता पर भी नजर रखती है ताकि, यह सुनिश्चित हो सके कि, वे भविष्य की शिक्षा के लिए तैयार हैं अथवा नहीं।
3. यह शिक्षार्थियों की सीखने की प्रगति पर भी नजर रखता है ताकि, यह सुनिश्चित हो सके कि, वे भविष्य में आवश्यक जीवन कौशल की शिक्षा के लिए तैयार हैं अथवा नहीं।

उल्लास मोबाईल एप्प ने 1.50 करोड़ से ज्यादा शिक्षार्थियों और 37 लाख स्वयंसेवी शिक्षकों को जोड़ा है, जो इस पहल की व्यापक पहुँच और प्रभाव को दर्शाता है –

क्र.सं.	तारीख	राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया	उपस्थित शिक्षार्थी	शिक्षार्थी प्रमाणित	उत्तीर्ण प्रतिशत
1	19.03.2023	11	2237510	2042174	91.27%
2.	24.09.2023	13	1757053	1575129	89.64%
3.	17.03.2024	23	3329704	2952385	88.6%
			7324267	6569688	3 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के परिणाम लंबित

- राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के चयनित नव–साक्षरों और स्वयंसेवी शिक्षकों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए विभाग ने 6 और 7 फरवरी 2024 को दो दिवसीय "उल्लास" मेला आयोजित किया, जिसका उद्घाटन माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया। "उल्लास" मेले के दौरान 22 भाषाओं में प्राइमर जारी किए गए।
- एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रुप में लद्दाख उल्लास के अन्तर्गत पूर्ण साक्षर होने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गयी है। 24 जून 2024 को आयोजित समारोह में माननीय उपराज्यपाल द्वारा इसकी घोषणा की गयी।
- नव–साक्षरों को जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से कौशल शिक्षा से जोड़ने के लिए 10 अक्टूबर 2023 को सचिव, डी.ओ.एस.ई.एल. और सचिव कौशल विकास एवं उद्यमिता द्वारा संयुक्त पत्र जारी किया गया।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वित्त वर्ष 2012–22 की बजट घोषणाओं के अनुरुप सभी के लिए शिक्षा (जिसे पहले प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता था) के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए वित्त वर्ष 2022–27 की अवधि के लिए एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना "उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ)" ... मंजूरी दी है। जिसके तहत "संसाधनों तक अधिक पहुँच सुनिश्चित करने

के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के सम्पूर्ण दायरों को कवर करने वाले ऑनलाईन मॉड्यूल पेश किए जाऐंगे"।

इस योजना का उद्देश्य न केवल बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है, बल्कि 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटकों को भी शामिल करना है, जैसे महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल।

"उल्लास" के तहत "मिजोरम" पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित :

मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री लालदुहोमा द्वारा 21 मई 2025 को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम "उल्लास" के तहत मिजोरम राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। इस उपलब्धि के अनुसार मिजोरम ने 98.20 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल की जो, किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के 95 प्रतिशत के मानक को पार कर गयी। इसके अन्तर्गत निरक्षर व्यक्तियों की पहचान के लिए 2023 में घर–घर जाकर एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद उल्लास योजना के तहत 1600 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

"उल्लास" के तहत "गोवा" दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित :

गोवा राज्य के 39वें राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सामंत द्वारा गोवा को नवभारत साक्षरता कार्यक्रम – उल्लास के अन्तर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। इस उपलब्धि के साथ गोवा भारत का दूसरा राज्य बन गया, जिसने राष्ट्रीय रुप से निर्धारित 95 प्रतिशत साक्षरता मानक को पार कर लिया और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रुप में अपनी पहचान फिर से साबित कर दी।

"उल्लास" के तहत "त्रिपुरा" तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित :

त्रिपुरा राज्य को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ नव–साक्षर शिक्षार्थियों और सामुदायिक हितधारकों द्वारा दिनांक 23 जून 2025 को उल्लास – नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, जो 2022 से 2027 तक लागू एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। उन्होंने बताया कि, उल्लास कार्यक्रम से त्रिपुरा की साक्षरता दर 95.6 प्रतिशत तक पहुँच गयी है जो कभी वर्ष 1961 में केवल 20.24 प्रतिशत हुआ करती थी। उल्लास कार्यक्रम की यह उपलब्धि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन में भी योगदान देती है।

उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून में शुभारम्भ :

अविकल उत्तराखण्ड समाचार वेबसाईट की खबर के अनुसार उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड राज्य के शिक्षामंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा एक सम्मेलन में शुरुआत की गयी। उल्लास–नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत एस.सी.ई.आर.टी. एवं एस.एल.एम.ए. के निदेशकों की यह राष्ट्रीय सम्मेलन देहरादून में आयोजित हुई थी। सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य को नशामुक्त तथा टी.बी. मुक्त राज्य बनाकर उत्तराखण्ड राज्य को पूर्ण शिक्षित बनाकर एक नयी पहचान दिलाना है।

उल्लास कार्यक्रम का उत्तराखण्ड राज्य के लिंगानुपात, साक्षरता स्तर एवं अन्य प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार कार्यक्षेत्र

तालिका संख्या 01 : उत्तराखण्ड की जनसंख्या

2011 की जनगणना के अनुसार	1.01 करोड़
2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख

दिए गए आँकड़ों के मुताबिक 2011 की जनगणना के अनुसार प्रस्तुत तालिका में दिए गए आँकड़े वर्ष 2001 की जनगणना आँकड़ों से अधिक है। अतः इस जनगणना में साक्षर और निरक्षर के साथ–साथ औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति शामिल हैं। अतः उल्लास कार्यक्रम का विस्तृत स्तर पर विशेष आवश्यकता है।

तालिका संख्या 2 : जनगणना आँकड़ों के अनुसार उत्तराखण्ड की जनसंख्या – महिला व पुरूष

2011 के अनुसार	उत्तराखण्ड की कुल जनसंख्या	10086292
	पुरुषों की जनसंख्या	5137773
	महिलाओं की जनसंख्या	4948519
2001 के अनुसार	उत्तराखण्ड की कुल जनसंख्या	8489349
	पुरुषों की जनसंख्या	4325924
	महिलाओं की जनसंख्या	4163425

उपरोक्त दिए गए आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में भी 2001 की भांति पुरुषों की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या तथा कुल जनसंख्या अधिक है। जिसमें साक्षर और निरक्षर के साथ–साथ औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति शामिल हैं। अतः उल्लास कार्यक्रम का विस्तृत स्तर पर विशेष आवश्यकता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार 2021 के आँकड़ों और रिपोर्ट के अनुसार कुछ अनुमानित साक्षरता दर –

कुल साक्षरता दर – 87.6%

पुरुष साक्षता दर – 94.3%

महिला साक्षरता दर – 80.7%

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की साक्षता दर –

साक्षरता दर – 78.82%

साक्षर लोगों की संख्या – 7,249,000

निरक्षर लोगों की संख्या – लगभग 2,296,000 (कुल जनसंख्या में से 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और साक्षर लोगों को घटाने के बाद प्राप्त आँकड़ों के अन्तर्गत)

(उत्तराखण्ड में निरक्षर लोगों की सटीक संख्या का अनुमान इस तरह लगाया गया है, क्योंकि, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखण्ड की कुल आबादी 10086292 थी और साक्षरता दर 78.82% थी।)

उत्तराखण्ड राज्य में "उल्लास" कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आँचलों में निवासरत आबादी को साक्षर बनाने के लिए एक संयुक्त प्रयास है।

उत्तराखण्ड के 13 जिलों में 2025–26 के लिए उल्लास कार्यक्रम हेतु लक्ष्य और बजटीय प्रावधान

उल्लास कार्यक्रम हेतु लक्ष्य – 196102 शिक्षार्थी

उल्लास कार्यक्रम हेतु बजट – 3,41,71,103.00 (3.417 करोड़)

बजट अनुमोदन – 2025.26

वर्ष	लक्षित शिक्षार्थी	FLN की लागत@165/ शिक्षार्थी	SCL/ SCERT	MME	स्वीकृत धनराशि
2025–26	1,96,102	3,23,56,830	5,00,000	13,14,273	3,41,71,103

उपरोक्त तालिका में वर्ष 2025–26 के प्राप्त आँकड़ों के अनुसार उत्तराखण्ड में उल्लास कार्यक्रम हेतु लक्ष्य 196102 शिक्षार्थियों को साक्षर बनाने का है जिसके लिए प्रस्तावित बजट रुपये तीन करोड़, इक्तालिस लाख, इकहत्तर लाख, एक सौ तीन मात्र है। जिसमें FLN की लागत एक सौ पैसठ रुपये प्रति शिक्षार्थी मात्र है।

उल्लास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धि में प्रगति –

उत्तराखण्ड राज्य में उल्लास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में शामिल किए गए पांच जिले इस प्रकार थे – हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, चम्पावत, उधमसिंह नगर।

उल्लास कार्यक्रम हेतु निर्धारित लक्ष्य –

वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में उल्लास कार्यक्रम का लक्ष्य – 1,36,000 शिक्षार्थी
वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में उल्लास कार्यक्रम का लक्ष्य – 1,28,923 शिक्षार्थी

उल्लास कार्यक्रम के अन्तर्गत मूल्यांकन परिणाम –

FLNAT की परीक्षा क्रमांक	परीक्षा आयोजन का वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण होने वाले शिक्षार्थियों की संख्या
पहला FLNAT की परीक्षा	सितम्बर 2023	13586	7077
दूसरा FLNAT की परीक्षा	मार्च 2024	13502	10983
तीसरा FLNAT की परीक्षा	सितम्बर 2024	9459	8103
चौथा FLNAT की परीक्षा	मार्च 2025	7988	परिणाम अपेक्षित है

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र, चढ़ीगांव, जिला – पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त आँकड़ों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में FLNAT की परीक्षा चार चरणों का आयोजित की गयी जिसमें सितम्बर 2023 में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में काफी अन्तर है। जबकि सितम्बर 2024 में आयोजित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अपेक्षितरूप से बहुत कम है।

उल्लास कार्यक्रम के तहत कार्यात्मक साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षण –

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालययी संस्थान ने उल्लास कार्यक्रम के अन्तर्गत 23 मार्च 2025 को आयोजित उत्तराखण्ड और पंजाब राज्य के कार्यात्मक साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम दिनांक 26 जून 2025 को घोषित कर दिया। कुल 61812 प्रौढ़ शिक्षार्थी मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हुए थे और उनमें से 59862 शिक्षार्थियों को साक्षर प्रमाणित किया गया। परिणाम NIOS की वेबसाईट www.nios.ac.in अथवा https://results.nios.ac.in पर भी उपलब्ध है। लिंगवार परिणाम आँकड़े इस प्रकार हैं–

लिंग	उत्तराखण्ड राज्य एवं पंजाब राज्य का उल्लास कार्यक्रम के तहत कार्यात्मक साक्षरता संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षण			
	उपस्थिति	सफल/उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत	सुधार की आवश्यकता है
पुरुष	19050	18699	98.16	351
महिला	42762	41163	96.26	1599
योग	61812	59862	96.85	1950

उत्तराखण्ड में उल्लास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं –

वयस्कों को सशक्त बनाना – इसका लक्ष्य सभी पृष्ठभूमियों के वयस्कों को सशक्त बनाना है ताकि वे अपने समाज में एकीकृत हो सकें और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें।

हाईब्रिड लर्निंग – यह कार्यक्रम हाईब्रिड दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिससे स्वयंसेवकों के लिए व्यक्तिगत रुप से प्रशिक्षण और अभिविन्यास सत्र आयोजित किए जाते हैं। शिक्षार्थी उल्लास मोबाईल ऐप और ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से शैक्षिक सामग्री तक पहुँच सकते हैं।

सामाजिक चेतना केन्द्र – विद्यालयों को अक्सर शाम के समय "सामाजिक चेतना(जागरुकता) केन्द्र" में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि, वे समुदाय–केन्द्रित शिक्षण केन्द्र के रुप में कार्य कर सकें।

मूल्यांकन और प्रमाणन – इस योजना के तहत पंजीकृत शिक्षार्थी वर्ष में दो बार आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा देते हैं। उत्तीर्ण होने पर उन्हें एक प्रमाणपत्र भी दिया जाता है।

स्थानीय सहभागिता – उत्तराखण्ड में जागरुकता पैदा करने और भागीदारी बढ़ाने के लिए उल्लास मेला जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे शिक्षार्थियों, स्वयंसेवकों और स्थानीय अधिकारियों को एक साथ लिया जा सके।

उत्तराखण्ड उल्लास कार्यक्रम को कैसे क्रियान्वित करना है –

जागरुकता अभियान – साक्षर समाज के निर्माण हेतु अक्टूबर 2024 में देहरादून में उल्लास मेले का आयोजन किया गया। उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत सभी जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा उल्लास पर विभिन्न सरकारी विद्यालयों जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तर पर कार्डिनेटर तैयार किया जा रहा है। इसके साथ–साथ जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल स्तर पर प्रत्येक विद्यालयों से किसी एक शिक्षक को उल्लास के अन्तर्गत एक स्वयंसेवी शिक्षक को तैयार कर उन्हें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र (डायट) के माध्यम प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं उन्हें उल्लास में स्वयंसेवी शिक्षकों के रुप में उल्लास ऐप में जोड़कर ऑनलाईन प्रशिक्षण दिए जाने सम्बन्धी निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र (डायट) को प्राप्त विद्यालयी शिक्षा से वंचित छात्र–छात्राओं की गोपनीय सूची काफी विस्तृत है। इस सूची के तहत आने वाले सभी शिक्षार्थियों को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से साक्षर बनाया जाना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड में उल्लास कार्यक्रम की विशष आवश्यकता है।

उल्लास मोबाईल ऐप द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक पूरे भारत में पंजीकृत शिक्षार्थियों की संख्या 3,07,34,271 है। पंजीकृत स्वयंसेवकों की संख्या 46,35,682 है। प्रमाणित नव–साक्षरों की संख्या 1,58,14,037 है तथा कुल आगन्तुकों की संख्या 45,53,462 है।

पंजीकरण अभियान – आज के समय में मोबाईल हर एक व्यक्ति की विशेष आवश्यकता बन गयी है। इसलिए साक्षर हो या असाक्षर, सभी को मोबाइल का उपयोग करना पड़ रहा है। ऐसे में उल्लास ऐप से हर एक व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गया है अथवा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, को उल्लास ऐप के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। उल्लास के तहत नियुक्त कार्डिनेटर इस ऑनलाईन माध्यम से हीं शिक्षार्थियों को उनके शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

परिणाम घोषित – राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड के लिए उल्लास कार्यक्रम के अन्तर्गत आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा के

परिणाम आधिकारिक रुप से घोषित कर दिए गए हैं तथा अधिकारिक दस्तावेज राज्य सरकार के साथ साझा कर दिए गए हैं।

उल्लास कार्यक्रम का निष्कर्ष

उल्लास कार्यक्रम का निष्कर्ष आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह सिर्फ साक्षरता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक के उन सभी नागरिकों को बुनियादी शिक्षा और जीवन कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाना है, जिन्हें औपचारिक शिक्षा का अवसर नहीं मिला है। यह सिर्फ एक साक्षरता कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि एक जन आन्दोलन है जो भारत के हर व्यक्ति को कार्यात्मक साक्षरता (पढ़ना, लिखना व अंक ज्ञान) के साथ हीं साथ अन्य महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल (डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जागरुकता, बाल देखभाल और शिक्षा, परिवार कल्याण आदि), व्यावसायिक कौशल विकास (स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से), बुनियादी शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक स्तर की समकक्षता सहित) और सतत शिक्षा (कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन में समग्र वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ–साथ स्थानीय शिक्षार्थियों के लिए रुचिकर या उपयोगी अन्य विषय, जैसे महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल पर अधिक उन्नत सामग्री सहित) सिखाकर सशक्त बनाना चाहता है। इस कार्यक्रम के सफल होने के लिए स्वैच्छिक भागीदारी, डिजिटल माध्यमों जैसे उल्लास मोबाईल ऐप आदि का उपयोग और निरन्तर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है।

उत्तराखण्ड राज्य में उल्लास कार्यक्रम के तहत अभी कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं प्राप्त हुआ है बल्कि यह एक चल रही केन्द्र प्रायोजित योजना है जो 2022 से 2027 तक लागू है। उत्तराखण्ड में भी, शिक्षा विभाग और अन्य संस्थान साक्षरता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर और स्वयंसेवकों की मदद से इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए आज भी काम कर रहे हैं और अच्छे निष्कर्ष के लिए प्रयासरत हैं। रुद्रपुर और देहरादून जैसे स्थानों पर साक्षरता कार्यकर्त्ताओं (स्वयंसेवी/टीचर्स) के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

उल्लास के अन्य उद्देश्यों के अन्तर्गत –

- उत्तराखण्ड राज्य के 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों को प्रभावी ढंग से साक्षर बनाना है।

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 42

- फरवरी 2025 में देहरादून में उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के निदेशकों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें उत्तराखण्ड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के प्रतिनिधियों ने अपने–अपने अनुभव साझा किए।
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड ने कार्यक्रम के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया है। यह पाठ्यक्रम राज्य की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि साक्षरता के प्रति रुचि जगाई जा सके।
- उल्लास कार्यक्रम के तहत न केवल बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान सिखाया जाता है बल्कि महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल, जैसे डिजिटल और वित्तीय साक्षरता पर जोर दिए जाने से शिक्षार्थियों के जीवन और आजीविका में सुधार हो रहा है।

References:

1. https://www.google.com/search?q=ullas+ek+parichay
2. https://www.google.com/search?q=ullas+word+origin
3. https://www.google.com/search?q=ullas+ke+ghatak
4.chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ncert.nic.in/flipbook/ullas/ ullas_file.pdf
5. https://ullas.education.gov.in/nilp/about-us
6.https://www.google.com/search?q=Foundation+Literacy+and+Numeracy+Assessment+Test
7. https://hindicurrentaffairs.adda247.com/goa-declared-fully-literate-under-ullas/
8.https://www.google.com/search?q=the+mizoram+state+was+declared+100+percent+literacy
9. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2139103#:~
10.https://avikaluttarakhand.com/uttarakhand/ullas-navbharat-literacy-program-launched-in-doon/
11. https://www.census2011.co.in/census/state/uttarakhand.html
12. https://www.kasigaschool.com/blog/why-dehradun-is-the-ideal-city-for-qualityeducation/#:~:text=Dehradun%20and%20education%20go%20hand,of%20North%20India
13.https://www.google.com/search?q=ullas+program+in+uttarakhand+state+government
14. Based on the materials and information obtained from DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING CERNTRE (DIET), VILLAGE - CHEDIGAON, PAURI GARWHAL, UTTARAKHAND
15. https://www.google.com/search?q=varsh+2021+ki+janganana+ke+anusar+india+mein+literate+and+illiterate+ki+sankhya

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 43

16. https://www.google.com/search?q=varsh+2021+ki+jangarna+ke+anusar+uttarakhand+state+mein+literate+aur+illiterate+ki+sankhya
17. https://www.google.com/search?q=ullas+program+conclusion+in+india
18.https://www.google.com/search?q=ullas+program+conclusion+in+uttarakhand+state
19. https://www.india.gov.in/spotlight/ullas-understanding-lifelong-learning-all-society
20. https://ullas.education.gov.in/nilp/whats-new

❍❍❍❍❍

PROUDH SHIKSHA
Form IV

1.	Place of Publication	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
2.	Periodicity of Publication	Biannual
3.	Printer's name Nationality Address	Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
4.	Publisher's name Nationality Address	Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
5.	Editor's name Nationality Address	Suresh Khandelwal Indian 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002
6.	Name and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders, holding more than one percent of the total capital	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002

I, Suresh Khandelwal, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated: 29-6-2026

Sd/-
Suresh Khandelwal
Publisher

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 44

उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण : एक समग्र दृष्टिकोण

– सुरेखा खोत

शिक्षा समाज की रीढ़ होती है और यह किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जो मुख्यरूप से सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित है, छात्रों को व्यावहारिक कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करने में अक्सर विफल रहती है। इस कमी को पूरा करने के लिए "उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण" एक महत्वपूर्ण कदम बनकर उभरा है। इसका उद्देश्य छात्रों को उन कौशलों से सुसज्जित करना है जो उन्हें उद्योग और रोजगार की मांगों के अनुरूप तैयार करे।

उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण क्या है?

उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और कौशल–आधारित प्रशिक्षण को शामिल करने की प्रक्रिया है। यह छात्रों को उद्योगों में सीधे उपयोग होने वाले कौशल, तकनीकी दक्षता और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा को रोजगार–उन्मुख बनाना और छात्रों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसरित करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में व्यावसायिक शिक्षा का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्राचीन काल से ही गुरूकुल शिक्षा प्रणाली में छात्रों को शास्त्रों के साथ–साथ व्यावसायिक कौशल जैसे कृषि, शिल्प, और युद्धकला की शिक्षा दी जाती थी। आधुनिक युग में अंग्रेजों ने व्यावसायिक शिक्षा को औद्योगिक क्रांति के तहत एक नया स्वरूप प्रदान किया। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की। लेकिन आज भी यह शिक्षा प्रणाली अपने पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर सकी है। सरकार सहित इसके सभी हितधारकों का प्रयास है कि शिक्षा का व्यावसायीकरण अपने अपेक्षित व्याप को छू सके ताकि अधिक से अधिक छात्र युवा इससे लाभान्वित हो आर्थिकरूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता

1. **बेरोजगारी की समस्या** : भारत में बढ़ती बेरोजगारी एक प्रमुख चिंता का विषय है। यहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकांश युवा भी रोजगार के लिए आवश्यक कौशल से वंचित रह जाते हैं।
2. **तकनीकी प्रगति** : आधुनिक युग में तकनीकी विकास ने उद्योगों की कार्यप्रणाली को बदल दिया है। इसके लिए छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना आवश्यक है।
3. **वैश्विक पतिस्पर्धा** : वैश्वीकरण के युग में, भारतीय छात्रों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करना आवश्यक है। व्यावसायिक शिक्षा उन्हें इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है।
4. **उद्यमशीलता का विकास** : व्यावसायिक शिक्षा छात्रों में उद्यमशीलता के गुणों का विकास

करती है जिससे वे नौकरी मांगने वाले के बजाय, नौकरी देने वाले बन सकते हैं।

उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण के लाभ

1. **रोजगार के अवसर** : व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को उद्योगों की मांग के अनुसार तैयार करती है, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं।
2. **व्यावहारिक ज्ञान** : यह प्रणाली छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ–साथ व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करती है।
3. **आत्मनिर्भरता** : व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें अपने कौशल का उपयोग करके स्वरोजगार उत्पन्न करने के अवसर प्रदान करती है।
4. **राष्ट्रीय विकास** : एक कुशल कार्यबल देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण की चुनौतियां

1. **बुनियादी ढांचे की कमी** : व्यावसायिक शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों और सुविधाओं की कमी एक बड़ी बाधा है।
2. **शिक्षकों की कमी** : व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
3. **सामाजिक पूर्वाग्रह** : व्यावसायिक शिक्षा को अब भी पारंपरिक शिक्षा से कमतर माना जाता है, जिससे इसके प्रति छात्रों और अभिभावकों में रूचि कम होती है।
4. **उद्योग और शिक्षा के बीच अंतर** : उद्योगों की मांग और शिक्षा प्रणाली के बीच तालमेल की कमी है।

व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करने के उपाय

1. **नीतियों का निर्माण** : सरकार को व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सशक्त नीतियां बनानी चाहिए।
2. **सार्वजनिक–निजी भागीदारी** : उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
3. **शिक्षा का आधुनिकीकरण** : पाठ्यक्रमों को आधुनिक उद्योगों की मांगों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।
4. **सामाजिक जागरूकता** : व्यावसायिक शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के उदाहरण

1. तकनीकी पाठ्यक्रम : कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, ऑटोमेशन।
2. सेवा क्षेत्र : होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, हेल्थकेयर।
3. उद्योग आधारित पाठ्यक्रम : मशीन ऑपरेशन, इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन।
4. कला और शिल्प : फैशन डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल ज्वैलरी निर्माण।

व्यावसायीकरण के प्रभाव

1. **सामाजिक बदलाव** : व्यावसायिक शिक्षा ने समाज में कौशल–आधरित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है।
2. **उद्योग के लिए लाभ** : उद्योगों को कुशल कार्यबल मिलने से उत्पाकदता और गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
3. **छात्रों के लिए अवसर** : यह प्रणाली छात्रों को विविध क्षेत्रों में कैरियर बनाने के अवसर प्रदान करती है।
4. **समाजिक समानता** : व्यावसायिक शिक्षा से सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर मिलते हैं।

भारत में व्यावसायीकरण की स्थिति

भारत में व्यावसायिक शिक्षा अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है। सरकार और निजी संस्थान इसके विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

1. सरकारी योजनाएं : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेसन (एनएसडीसी) और अन्य योजनाएं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू की गयी हैं।
2. निजी भागीदारी : कई निजी संस्थान और उद्योग भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।
3. चुनौतियां : छात्रों और अभिभावकों में जागरूकता की कमी, बुनियादी ढ़ांचे का अभाव, और योग्य शिक्षकों की कमी।

व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार

व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को रोजगार–उन्मुख बनाना है। यह प्रणाली छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रदान करती है, जो उन्हें विभिन्न उद्योगों में रोजगार के लिए तैयार करती है।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण वर्तमान समय की मांग है। यह न केवल छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करता है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और उद्यमशीलता की ओर भी अग्रसरित करता है। हालांकि इसके समुचित कार्यान्वयन के लिए नीतिगत समर्थन, संसाधनों का विकास और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए, तो व्यावसायिक शिक्षा भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है और देश को आर्थिक और सामाजिकरूप से सशक्त बना सकती है।

विस्तार की संभावनाएं

व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े आंकड़ों, नीतियों और क्षेत्रीय प्रयासों पर अधिक जानकारी इस अध्ययन को और अधिक प्रासंगिक बना सकती है। उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण के संदर्भ में सांख्यिकीय डेटा का समावेश इस विषय की गहन समझ प्रदान करता है। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी है, जो निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होती है:

उच्च शिक्षा संस्थानों और नामांकन में वृद्धि

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि : स्वतंत्रता के बाद से, भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या में 40 गुना, महाविद्यालयों में 80 गुना और विद्यार्थियों की संख्या में 80 गुना तथा शिक्षकों की संख्या में 30 गुना वृद्धि हुई है।

सकल नामांकन अनुपात : वर्ष 2002–03 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 9 प्रतिशत था, जो 2013–14 में बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत, 2020 तक सकल नामांकन अनुपात को 30 प्रतिशत तक बढाने का लक्ष्य रखा गया था।

छात्र नामांकन : वर्ष 2021–22 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्र नामांकन की संख्या 3.42 करोड़ थी, जो 2024–15 में 4.33 करोड़ हो गयी। यह उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है। उच्च शिक्षा में नामांकित महिलाओं की संख्या 2021–22 में 2.07 करोड़ थी, जो 2014–15 में 1. 5 करोड़ से 32 प्रतिशत अधिक है।

निजी संस्थानों की भूमिका

निजी महाविद्यालयों की संख्या : वर्ष 2014 तक, भारत में कुल 36,812 महाविद्यालय थे, जिनमें से 20,390 निजी और 6,768 सरकारी महाविद्यालय थे।

निजी क्षेत्र का योगदान : उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है, जो छात्रों को विविध व्यावसायिक पाठयक्रमों में नामांकन के अवसर प्रदान करती है।

व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति

व्यावसायिक शिक्षा का समावेश : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा।

कौशल विकास : सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा सके।

चुनौतियां

बेरोजगारी : विकासशील देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी की दर विकसित देशों की तुलना में दो से तीन गुना अधिक है। कई नए शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि स्नातक रोजगार बाजार के लिए पर्याप्तरूप से तैयार नहीं हो पा रहे हैं।

शिक्षकों की संख्या में वृद्धि : वर्ष 2013–14 से 2021–22 के बीच शिक्षकों की संख्या में केवल 17 प्रतिशत (23,0153) की वृद्धि हुई, जो कि 2 प्रतिशत की मामूली वार्षिक वृद्धि है।

उपरोक्त आंकड़े उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण की दिशा में भारत की प्रगति और उससे संबंधित चुनौतियों के स्पष्ट करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के समावेश से छात्रों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करने में मद्द मिलती है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। हालांकि, गुणवत्ता, अभिगम्यता और शिक्षकों की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है ताकि उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण सफल हो सके।

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 48

हमारे लेखक

श्री राजेन्द्र जोशी
तपसी भवन
नाथूसर बास, बंगुला नगर
बीकानेर, राजस्थान – 334 004

डॉ विमलेश सिंह
अतिथि विद्वान, अर्थशास्त्र
शासकीय महाविद्यालय पिछोर,
जिला–ग्वालियर,
(मध्य प्रदेश.)

डॉ. संदीप कुमार
सहायक प्रोफेसर
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
दरियागंज (एस सी ई आर टी)
नई दिल्ली

डॉ. अशोक कुमार
सहायक प्रोफेसर
शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार
विभाग, रा.शै.अ.प्र. प.
नई दिल्ली

डॉ. सुकांत कुमार महापात्रा
एसोसिएट प्रोफेसर
शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार
विभाग, रा.शै.अ.प्र. प.
नई दिल्ली

डॉ. अनिता जोशी
प्रोफेसर, बी. एड. विभाग
एम.बी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल
उत्तराखंड – 263 139

डॉ. माया जोशी
असिस्टेंट प्रोफेसर, बी. एड. विभाग
एम.बी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल
उत्तराखंड – 263 139

डॉ. सौरभ मिश्र
सहायक अध्यापक
राजकीय इण्टर कालेज धोबीघाट
जिला पौड़ी गढ़वाल
उत्तराखण्ड – 246 155

श्रीमती सुरेखा खोत
'एएआई' बंग्लो
नजदीक सरकारी हॉस्पिटल
जिला बुलडाना
महाराष्ट्र – 443 001

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 49

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

संरक्षक
प्रो. एस. वाय. शाह

अध्यक्ष
प्रो. एल. राजा

उपाध्यक्ष
प्रो. अशोक भट्टाचार्य
प्रो. वी. रेघु
प्रो. पी. आदिनारायण रेड्डी
प्रो. सरोज गर्ग
श्री ए. एच. खान

महासचिव
श्री सुरेश खण्डेलवाल

कोषाध्यक्ष
प्रो. राजेश

संयुक्त सचिव
श्री मृणाल पन्त

सह–सचिव
डॉ. डी. उमा देवी
श्री राजेन्द्र जोशी
डॉ. आशा वर्मा
श्री वाई. एन. शंकरेगौडा

सदस्य
श्रीमती निशात फारूख
डॉ. गोरखनाथ नामदेव कांबले
श्री दुर्लभ चेतिया
डॉ. नीतीश आनंद
श्री सुधाकर मानसिंह सेंगर
श्री वी. उमर कोया
प्रो. ऋतु त्रिवेदी
डॉ. चयनिका उन्याल

सहयोजित सदस्य
प्रो. अजय कुमार
डॉ. एस.वी.ए. प्रकाश
डॉ. मनोज कुमार बेहरा

PS Jan-Jun 2026_feb'11 pror shiksha.qxd 6/25/2026 4:57 PM Page 50

प्रौढ़ शिक्षा जनवरी-जून 2026 आर.एन.आई. 4551/57



"जिस शिक्षा से मनुष्य अन्याय के विरूद्ध खड़ा नहीं हो सकता, वह शिक्षा नहीं गुलामी का पाठ है।"

– महात्मा ज्योतिबा फुले

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के लिए सुरेश खण्डेलवाल द्वारा 17–बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा मैसर्स – ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से मुद्रित।
सम्पादक : सुरेश खण्डेलवाल